नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 224
दि. 18.05.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से 'कल्पसर परियोजना' को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट 'कल्पसर प्रोजेक्ट' को मिले नीदरलैंड की तकनीक के नए पंख
- गुजरात की पानी की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी कल्पसर परियोजना
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नीदरलैंड दौरे के दौरान कल्पसर परियोजना के लिए तकनीकी सहयोग को लेकर आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए
- गुजरात को जल संसाधन के क्षेत्र में नीदरलैंड के तकनीकी सहयोग और विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा
- सरदार सरोवर बांध पर निर्भरता होगी कम, पेयजल और सिंचाई के लिए सुनिश्चित होगी जल की व्यापक उपलब्धता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। नीदरलैंड के अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री श्री रॉब जेटेन के साथ नीदरलैंड की प्रसिद्ध जल प्रबंधन संरचना, 'अफस्लुइटडिज्क' (Afsluitdijk) का दौरा किया। उन्होंने इस बांध में इस्तेमाल की गई तकनीक को सीखने योग्य बताया। उल्लेखनीय बात यह है कि 'अफस्लुइटडिज्क' और गुजरात की कल्पसर परियोजना के बीच बहुत-सी समानताएं हैं। कल्पसर परियोजना पर तकनीकी सहयोग के लिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भारत के जल शक्ति मंत्रालय और नीदरलैंड के बुनियादी ढांचा और जल प्रबंधन मंत्रालय के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इससे परियोजना का कार्य तेज रफ्तार से आगे बढ़ने के नए द्वार खुल गए हैं।

अनियमित वर्षा और सूखे की समस्या से वर्षों से जूझ रहे गुजरात को सरदार सरोवर बांध के निर्माण से राहत तो मिली है, लेकिन दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए

किसी एक परियोजना पर ही निर्भर रहना जोखिम ही कहा जा सकता है। इसीलिए, तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने खंभात की खाड़ी में महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना की संकल्पना की थी। हालांकि, यह परियोजना तकनीकी रूप से अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण है।

क्या है कल्पसर परियोजना

कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी में एक विशाल बांध का निर्माण कर समुद्र में गिर रहीं सात नदियों के पानी का उपयोग करने की योजना है। इस योजना का उद्देश्य खंभात की खाड़ी पर मीठे पानी का एक विशाल जलाशय बनाना है, जिसमें ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन, सिंचाई और परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर का एकीकृत विकास शामिल है।

वर्ष 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से कल्पसर बांध की पथरेखा सुनिश्चित करने के लिए भावनगर में समुद्री सर्वेक्षण का ऐतिहासिक शुभारंभ किया गया। लेकिन, योजना के बेहद जटिल होने के कारण इसे साकार करने में कई प्रकार की मुश्किलें सामने आ रही हैं। इन मुश्किलों से निपटने के लिए सरकार की ओर से लगातार ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में, 30 मार्च, 2026 को गांधीनगर में नीदरलैंड की राजदूत सुश्री मारिसा गेराड्र्स से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कल्पसर योजना को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की और 'इंडो-डच' विशेषज्ञ समूह के गठन और जी2जी भागीदारी के बारे में चर्चा की।

कल्पसर परियोजना से मिलेंगे ये लाभ

कल्पसर परियोजना के साकार होने पर सौराष्ट्र के 9 जिलों की 42 तहसीलों को लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलेगा। इस योजना से दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के बीच की दूरी 240 किलोमीटर से कम होकर 60 किलोमीटर रह जाएगी। इतना ही नहीं, योजना से लगभग 1500 मेगावाट पवन ऊर्जा और 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। योजना से पर्यटन और मत्स्य पालन का विकास भी सुनिश्चित होगा।

कल्पसर परियोजना को साकार करने के लिए समय-समय पर विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट भी तैयार की गई हैं। कल्पसर परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 'क्लोजर मेथेडोलॉजी' में नीदरलैंड के समुद्री क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाले विश्व प्रसिद्ध संस्थान 'रॉयल हास्कोनिंग' ने काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है।

क्या है 'अफस्लुइटडिज्क'

'अफस्लुइटडिज्क' नीदरलैंड ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे मशहूर इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक है। यह दुनिया के लिए जल प्रबंधन का एक शानदार उदाहरण है। इसका निर्माण लगभग 80 साल पहले किया गया था। ये 32 किलोमीटर लंबा बैरियर डैम उत्तरी सागर को मीठे पानी की झील से अलग करता है। साथ ही, यह बांध नीदरलैंड के निचले इलाकों के बड़े हिस्से को भारी बाढ़ से बचाता है, यही वजह है कि इसे बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक मानक माना जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह समुद्र के खारे पानी को रोककर अंदर मीठे पानी का एक बहुत बड़ा जलाशय बनाता है। 'अफस्लुइटडिज्क' परियोजना में मीठे पानी के भंडारण के अलावा जहाजरानी, परिवहन संपर्क और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन भी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री का दृढ़ संकल्प और नीदरलैंड की भागीदारी करेगी कल्पसर परियोजना को साकार

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सदैव दीर्घकालीन और बड़े लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते हैं। गुजरात में अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान उन्होंने कल्पसर परियोजना का स्वप्न देखा था। राज्य को जल संकट की स्थिति से बाहर निकालकर जल समृद्ध बनाने के संकल्प के साथ उन्होंने सरदार सरोवर बांध जैसी विराट परियोजना को धरातल पर उतारा। दशकों तक राजनीतिक और पर्यावरणीय अवरोधों का सामना कर रही सरदार सरोवर योजना को साकार करने के लिए उन्होंने अदम्य इच्छा शक्ति और फौलादी संकल्प का परिचय दिया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी कल्पसर योजना को लेकर शुरुआत से आशावादी रहे। तमाम प्रकार की अड़चनों के बावजूद उन्होंने इस परियोजना को साकार करने के स्वप्न को आंखों से ओझल नहीं होने दिया। जटिल इंजीनियरिंग और तकनीक की विराट चुनौतियों के कारण परियोजना में विलंब अवश्य हुआ, लेकिन हाल के नीदरलैंड दौरे के दौरान उनका जल प्रबंधन संरचना 'अफस्लुइटडिज्क' का निरीक्षण करने जाना और कल्पसर परियोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में भारत का नीदरलैंड के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर करना, यह बताता है कि प्रधानमंत्री कल्पसर परियोजना को लेकर कितने गंभीर और आशावादी हैं। इस बारे में भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा बयान में कहा गया है कि यह दौरा दोनों देशों की इस साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि वे जल प्रबंधन के नवाचार, जलवायु अनुकूलन और सतत अवसंरचना के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का यह दौरा और कल्पसर परियोजना के लिए हुए आशय पत्र पर हस्ताक्षर से गुजरात के लिए सुनहरी संभावनाओं के नए द्वार खुल गए हैं। इसके साथ ही, नीदरलैंड अपने विश्व प्रसिद्ध 'अफस्लुइटडिज्क' डैम प्रोजेक्ट के 90 वर्षों से अधिक के प्रबंधन के अनुभव और निपुणता का लाभ भारत को देगा। यह सहयोग 29 मार्च, 2022 को दोनों देशों के बीच हुई 'जल पर भारत-डच रणनीतिक साझेदारी' पर आधारित है। बता दें कि नीदरलैंड के पास समुद्र में बांध बनाने की उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञता है, और अब गुजरात को इसी विशेषता का लाभ मिलने जा रहा है, जो राज्य की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा।

दिल्ली में महिला उद्यमिता को बड़ा बढ़ावा, बिना गारंटी 10 करोड़ तक लोन की घोषणा से बदलेगा स्वरोजगार का परिदृश्य

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा और महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने घोषणा की है कि अब दिल्ली की महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और महिला स्टार्टअप्स को बिना किसी गारंटी के 10 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ऋण की गारंटी खुद दिल्ली सरकार लेगी, जिससे महिलाओं को बड़े स्तर पर उद्यम शुरू करने में आसानी होगी। इस घोषणा को महिला उद्यमिता को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को केवल सहायता देना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर उद्यमी के रूप में स्थापित करना है। उनका कहना है कि महिलाओं के छोटे-छोटे व्यवसायों को यदि सही वित्तीय सहायता और बाजार उपलब्ध कराया जाए तो वे बड़े उद्योगों के बराबर योगदान दे सकती हैं।

यह घोषणा उत्तर पश्चिम दिल्ली के रोहिणी स्थित यूनिटी वन मॉल में आयोजित दो दिवसीय मेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) मेला-2026 के उद्घाटन अवसर पर की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूहों ने भाग लिया और अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को बड़े बाजारों

तक पहुंच मिले और महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। सरकार की इस योजना को प्रधानमंत्री Narendra Modi के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' विजन से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की महिलाएं पहले से ही घरेलू उद्योग, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसायों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, लेकिन उन्हें विस्तार के लिए पूंजी और बाजार की जरूरत होती है। यह योजना उसी अंतर को भरने का प्रयास है। योजना के तहत विभिन्न बैंकिंग संस्थानों को भी जोड़ा जा रहा है ताकि महिलाओं को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वयं सहायता समूहों को केवल घोषणा तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें वास्तविक वित्तीय सहायता मिले। बैंकिंग सेक्टर की भागीदारी से ऋण प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने इस अवसर पर यह भी कहा कि दिल्ली सरकार महिलाओं के उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने के लिए मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में विशेष मंच उपलब्ध कराएगी। इससे महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, खादी उत्पाद, घरेलू सामान, क्रोशिया आइटम, खाद्य सामग्री और अन्य उत्पादों को सीधा ग्राहकों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण और ईंधन बचत से जुड़े अभियानों पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने 'मंडे मेट्रो' और 'नो व्हीकल डे' जैसे अभियानों का उल्लेख करते हुए कहा कि सार्वजनिक परिवहन के उपयोग से न केवल ईंधन की बचत होती है, बल्कि प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सकता है। उनका कहना था कि आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन भी उतना ही जरूरी है।

कार्यक्रम में लगभग 24 स्वयं सहायता समूहों ने हिस्सा लिया और अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। इनमें हस्तशिल्प, घरेलू उत्पाद, खादी वस्त्र, सजावटी सामान और पारंपरिक खाद्य उत्पाद शामिल थे। मेले में महिलाओं की भागीदारी और उत्साह ने यह दिखाया कि यदि उन्हें उचित अवसर मिले तो वे बड़े स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में योगदान दे सकती हैं।

इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें सांसद Yogendra Chandolia, विधायक Kulwant Rana और उत्तर पश्चिम जिले की डीएम Saumya Saurabh प्रमुख रूप से शामिल थे। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह योजना प्रभावी तरीके से लागू होती है तो दिल्ली में महिला उद्यमिता को एक नई गति मिल सकती है। बिना गारंटी बड़े लोन की सुविधा महिलाओं को छोटे व्यवसाय से आगे बढ़ाकर बड़े उद्योग स्थापित करने का अवसर दे सकती है। हालांकि, इसके सफल क्रियान्वयन के लिए बैंकिंग प्रक्रिया की पारदर्शिता और निगरानी बेहद महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल इस घोषणा को दिल्ली में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में हजारों महिलाओं के लिए स्वरोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता के नए रास्ते खुल सकते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के 'अरोनई' पहनने पर हिमंत सरमा का बयान, बोडो विरासत को मिला वैश्विक सम्मान

गुवाहाटी। नीदरलैंड के आधिकारिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा पारंपरिक बोडो स्कार्फ 'अरोनई' पहनने को लेकर असम में राजनीतिक और सांस्कृतिक हलकों में सराहना का दौर जारी है। असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma ने इस कदम को बोडो समुदाय की समृद्ध हथकरघा परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का वैश्विक सम्मान बताया है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 'अरोनई' केवल एक पारंपरिक वस्त्र नहीं है, बल्कि यह बोडो समुदाय की गौरवशाली विरासत, उनकी कला और हथकरघा संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के प्रधानमंत्री इस पारंपरिक स्कार्फ को सम्मान के साथ धारण करते हैं, तो यह पूरे समुदाय के लिए गर्व का क्षण बन जाता है।

दरअसल, यह दृश्य नीदरलैंड के हेग में उस समय देखने को मिला जब Narendra Modi प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पारंपरिक बोडो स्कार्फ 'अरोनई' पहना, जिसने वहां मौजूद भारतीय प्रवासियों के बीच विशेष आकर्षण पैदा किया। इस सांस्कृतिक प्रस्तुति को भारत

की विविधता और एकता के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma ने कहा कि यह क्षण केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि यह बोडोलैंड क्षेत्र में हुए सामाजिक और राजनीतिक बदलावों को भी दर्शाता है। उन्होंने 2020 के बोडो शांति समझौते का उल्लेख करते हुए कहा कि इस समझौते ने क्षेत्र में स्थायी शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। उनके अनुसार इस समझौते के बाद बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में उग्रवाद की समस्या काफी हद तक समाप्त हो चुकी है और विकास की नई शुरुआत हुई है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र Bodoland Territorial Region में अब शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास का नया युग शुरू हो चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से इस क्षेत्र में शिक्षा, बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों में सुधार हुआ है।

'अरोनई' को बोडो समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा माना जाता है। यह पारंपरिक रूप से हथकरघा तकनीक से बनाया जाता है और इसे सम्मान, स्वागत और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर इसके प्रदर्शन को विशेषज्ञ भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का हिस्सा मान रहे हैं, जिसके जरिए देश अपनी विविध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत कर रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि Narendra Modi का इस तरह पारंपरिक परिधानों को अपनाना न केवल सांस्कृतिक जुड़ाव का संकेत है, बल्कि यह भारत की 'सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी' को भी मजबूत करता है। इससे विभिन्न क्षेत्रीय समुदायों को राष्ट्रीय पहचान के साथ जोड़ने का संदेश भी जाता है। उधर, असम में बोडो समुदाय के कई संगठनों ने भी इस कदम का स्वागत किया है और इसे अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए वैश्विक पहचान का अवसर बताया है। उनका कहना है कि ऐसे प्रयासों से नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं और संस्कृति के प्रति गर्व महसूस होता है और हथकरघा उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। फिलहाल यह मामला राजनीतिक से ज्यादा सांस्कृतिक चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे प्रतीकात्मक कदम भारत की विविधता और एकता की छवि को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर और मजबूत करते हैं।

केरल में ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन, UDF सरकार का भव्य शपथ ग्रहण आज, 21 मंत्रियों के साथ नई कैबिनेट तैयार

नई दिल्ली। केरल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव दर्ज करते हुए United Democratic Front (UDF) की नई सरकार का शपथ ग्रहण आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव में 140 में से 102 सीटों के साथ मिली प्रचंड जीत के बाद राज्य में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं और अब नई सरकार औपचारिक रूप से सत्ता संभालने जा रही है। इस ऐतिहासिक मौके को लेकर राज्यभर में राजनीतिक हलचल तेज है और इसे केरल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

नई सरकार का नेतृत्व कर रहे नेता V. D. Satheesan ने रविवार को राज्यपाल को 20 मंत्रियों की सूची सौंप दी, जिसके बाद उनके नाम को जोड़कर कुल 21 सदस्यीय मंत्रिमंडल तैयार हो गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी मंत्रियों के नामों को पार्टी हाईकमान की मंजूरी के बाद अंतिम रूप दिया गया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कैबिनेट गठन

की प्रक्रिया आसान नहीं थी, क्योंकि कई वरिष्ठ और योग्य नेताओं को भी जगह नहीं मिल पाई, जिससे संगठन के भीतर संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहा।

V. D. Satheesan ने कहा कि मंत्रिमंडल का गठन केवल राजनीतिक योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उन्होंने बताया कि केरल जैसे विविधतापूर्ण राज्य में हर क्षेत्र और समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना आवश्यक था, इसलिए कुछ नेताओं को इस बार अवसर नहीं मिल सका, हालांकि उनका योगदान पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। नई कैबिनेट में सबसे अधिक मंत्री पद Indian National Congress के हिस्से में आए हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिनमें Ramesh Chennithala, K. Muraleedharan, सनी जोसेफ, बिंदु कृष्णा, एपी अनिल कुमार, पीसी विष्णुनाथ, एम लिजू, रोजी एम जॉन, टी सिद्दीक, ओजे जनीश और केए तुलसी जैसे नाम शामिल हैं। इन नेताओं को राज्य प्रशासन के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है।

गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। Indian Union Muslim League (IUML) से पीके कुन्हालीकुट्टी, पीके बशीर, एन शम्सुद्दीन, केएम शाजी और वीई अब्दुल गफूर को मंत्री पद दिया गया है। इसके अलावा Kerala Congress से मॉन्स जोसेफ, Revolutionary Socialist Party से शिबू बेबी जॉन, Kerala Congress (Jacob) से अनूप जैकब और Communist Marxist Party से सीपी जॉन को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इस तरह गठबंधन के सभी प्रमुख घटकों को प्रतिनिधित्व देकर सरकार ने व्यापक राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की है।

शपथ ग्रहण समारोह को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं और इसे एक बड़े राजनीतिक आयोजन के रूप में देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी भी चर्चा में है। पार्टी अध्यक्ष Mallikarjun Kharge और वरिष्ठ नेता Rahul Gandhi के शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा Priyanka Gandhi Vadra के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है, जबकि पूर्व अध्यक्ष Sonia Gandhi की उपस्थिति को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

सूत्रों के अनुसार कांग्रेस शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी इस समारोह में शामिल हो सकते हैं, जिनमें कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रमुख रूप से शामिल बताए जा रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay को भी आमंत्रण भेजा गया है, हालांकि उनकी उपस्थिति की पुष्टि अभी नहीं हुई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि United Democratic Front की यह जीत केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि केरल की राजनीति में एक नए जनादेश और राजनीतिक पुनर्गठन का संकेत है। भारी बहुमत के साथ मिली जीत ने गठबंधन को मजबूत जनसमर्थन दिया है, और अब नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती चुनावी वादों को धरातल पर उतारने की होगी।

नई सरकार से जनता की उम्मीदें भी काफी बढ़ी हुई हैं, खासकर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी जीत के बाद सरकार पर प्रदर्शन का दबाव भी उतना ही अधिक रहेगा। प्रशासनिक सुधार, निवेश बढ़ाने और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने जैसे मुद्दे आने वाले समय में सरकार की प्राथमिकताओं में रहेंगे।

फिलहाल पूरे राज्य की निगाहें सुबह 10 बजे होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हुई हैं, जिसे केरल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है।

नवसर्जन संस्कृति हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

देशभक्ति अब त्याग की नई सरकारी परिभाषा बन गई है

देशभक्ति का अर्थ समय-समय पर बदलता रहा है। कभी देशभक्ति का मतलब आजादी के लिए जेल जाना था, कभी सीमाओं पर लड़ना था, कभी सत्य और न्याय के लिए आवाज उठाना था। लेकिन अब देशभक्ति का नया संस्करण सामने आया है, जिसमें त्याग तो है, लेकिन त्याग करने वाले आम लोग हैं और लाभ उठाने वाले वही पुराने खास लोग। अब देशभक्त बनने के लिए न सीमा पर जाना जरूरी है, न क्रांति करनी है, न सत्ता से सवाल पूछना है। अब बस इतना करना है कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम खर्च करो, तेल कम खाओ और हर बढ़ती हुई कीमत पर मुस्कुराते हुए कहो—देशहित में सब मंजूर है। यह सचमुच बड़ा सुलभ अवसर है। क्योंकि पहले देशद्रोही बनने के आरोप बहुत आसानी से लग जाते थे। किसान अपनी फसल का उचित दाम मांगे तो देशद्रोही, मजदूर वेतन बढ़ाने की बात करे तो देशद्रोही, छात्र शिक्षा और रोजगार की मांग करें तो देशद्रोही। यहां तक कि अगर कोई नागरिक सरकार की किसी नीति पर सवाल उठा दे, तब भी उसके देशप्रेम पर संदेह होने लगता था। ऐसा लगता था कि देश में समस्याएं कम और देशद्रोही ज्यादा पैदा हो रहे हैं। लेकिन अब माहौल बदल रहा है। अब सरकार और समाज दोनों मिलकर लोगों को देशभक्त बनने के आसान उपाय बता रहे हैं। सोना मत खरीदिए। यह देशभक्ति है। हालांकि आम आदमी पहले ही सोने की कीमत देखकर घबराया हुआ है। मध्यम वर्ग तो अब गहनों की दुकान के सामने से गुजरते समय भी अपने बजट का हिसाब लगाने लगता है। लेकिन फिर भी भारतीय समाज में शादी-ब्याह और त्योहारों में सोना सिर्फ धातु नहीं, प्रतिष्ठा और परंपरा का हिस्सा माना जाता रहा है। बहू-बेटी को गहने देना सामाजिक सम्मान का प्रतीक रहा है। अब अगर कोई परिवार सोना न खरीदे तो यह आर्थिक मजबूरी नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में लिया गया फैसला माना जाएगा। पहले लोग कहते थे—"सादा शादी हुई है।" अब कहेंगे—"देशभक्तिपूर्ण शादी हुई है।" इसी तरह विदेश यात्रा को देखिए। आम आदमी तो पासपोर्ट बनवाने तक में वर्षों निकाल देता है। विदेश यात्रा आज भी देश की बड़ी आबादी के लिए सपना ही है। लेकिन अब जो लोग विदेश नहीं जाएंगे, वे भी गर्व से कह सकेंगे कि वे देशहित में त्याग कर रहे हैं। नेता और अफसरों की विदेश यात्राएं तो हमेशा राष्ट्रनिर्माण का हिस्सा मानी जाती हैं, लेकिन जो युवा बेहतर अवसरों के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनकी मजबूरियां कभी देशभक्ति नहीं मानी गईं। कंटेनरों में भरकर, डंकी रूट से या कबूतरबाजी के जरिए विदेश जाने वाले युवाओं को हमेशा अपराधी नजरों से देखा गया। जबकि सच यह है कि वे सिर्फ बेहतर जिंदगी की तलाश में निकलते हैं। अब अगर वही युवा विदेश जाने का सपना छोड़ दें, तो शायद उन्हें पहली बार देशभक्त कहलाने का मौका मिल जाए। देशभक्ति का यह नया मॉडल बड़ा दिलचस्प है। इसमें संघर्ष नहीं, सहनशीलता चाहिए। सवाल मत पूछिए, बस त्याग कीजिए। महंगाई बढ़े तो खर्च कम कर दीजिए, टैक्स बढ़े तो चुप रहिए, सुविधाएं घटें तो उसे आत्मनिर्भरता मान लीजिए। पेट्रोल महंगा हो जाए तो बाइक कम चलाइए और इसे पर्यावरण प्रेम तथा राष्ट्रप्रेम दोनों घोषित कर दीजिए। रसोई गैस महंगी हो जाए तो कम खाना पकाइए और इसे सादगी का उत्सव कह दीजिए। तेल कम खाइए, दाल कम खाइए, घूमना कम कीजिए—हर कटौती को देशभक्ति का तमगा मिल सकता है। धीरे-धीरे ऐसा माहौल बनता जा रहा है जिसमें नागरिकों की परेशानियों को भी राष्ट्रीय कर्तव्य में बदल दिया जाता है। बेरोजगारी है तो धैर्य रखिए, यह देशहित में है। महंगाई है तो सहन कीजिए, यह आत्मनिर्भरता की कीमत है। सुविधाएं कम हैं तो संतोष रखिए, यही असली राष्ट्रधर्म है। यानी जनता जितना ज्यादा त्याग करेगी, उतनी ज्यादा देशभक्त मानी जाएगी। दूसरी तरफ सत्ता, वैभव और विशेषाधिकार वैसे ही बने रहेंगे, क्योंकि उनका देशप्रेम शायद अलग श्रेणी का होता है। विडंबना यह है कि सच्ची देशभक्ति का मतलब कभी भी सिर्फ त्याग नहीं रहा। सच्ची देशभक्ति का मतलब था देश को बेहतर बनाने की कोशिश करना। गलत को गलत कहना, व्यवस्था से सवाल पूछना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना और समाज में समान अवसर सुनिश्चित करना भी देशभक्ति ही है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि देशभक्ति को धीरे-धीरे एक भावनात्मक अनुशासन में बदला जा रहा है, जिसमें नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य सिर्फ सहन करना रह गया है।

परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता व जवाबदेही तय हो

> "पेपर लीक पर नियंत्रण सिस्टम की मजबूती, भ्रष्टाचार नियंत्रण, तकनीकी उपयोग और सामाजिक मूल्य समृद्ध करने से होगा, जहां मेरिट व कौशल को सर्वोच्च महत्व दिया जाए।

हाल ही में नीट परीक्षा के पेपर लीक की घटना ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। वर्षों से नीट, जेईई, यूपीएससी, एसएससी और विभिन्न राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षाओं में बार-बार होने वाले पेपर लीक युवाओं के भविष्य के साथ निरंतर खिलवाड़ बन गए हैं।

छात्र-छात्राएं रात-दिन की मेहनत, परिवार का आर्थिक बलिदान और कोचिंग संस्थानों पर खर्च के बावजूद एक संगठित गिरोह की वजह से अपनी मेहनत को व्यर्थ होते देखते हैं। पिछले पांच वर्षों में 15 राज्यों में 41 प्रमुख परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जिनसे करीब 1.4 करोड़ युवा प्रभावित हुए। सात वर्षों की अवधि में यह संख्या 70 से अधिक पहुंच गई है और लगभग 1.7 करोड़ अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। यह समस्या केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रतिभा और मेरिट को कमजोर करने वाली है। जब चिकित्सा, इंजीनियरिंग और प्रशासनिक सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अयोग्य उम्मीदवारों का चयन होता है, तो समाज और देश दोनों को दीर्घकालिक क्षति पहुंचती है। युवा पीढ़ी में निराशा बढ़ती है, कई बार आत्महत्या जैसे कदम भी उठाए जाते हैं। कोचिंग माफिया, भ्रष्ट अधिकारी, प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी और डिजिटल नेटवर्क मिलकर एक शक्तिशाली गिरोह का रूप ले चुके हैं। गरीब छात्र बिना संसाधनों के तैयारी करते हैं, जबकि साधन रखने वाले लीक पेपर खरीदकर सफलता हासिल कर लेते हैं। इससे सामाजिक असमानता बढ़ती है और मेरिट की जगह सिफारिश और पैसा हावी हो जाता है। परिणामस्वरूप सही प्रतिभा को अवसर नहीं मिल पाता।

इस समस्या को समाप्त करने के लिए सशक्त और देश में एकसमान कानून की तत्काल जरूरत है। वर्तमान में लागू पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट में तीन से दस वर्ष की जेल और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन इसका क्रियान्वयन कमजोर रहा है। नए कानून में परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति—प्रश्न सेटर, प्रिंटर, परिवहनकर्ता और केंद्र अधीक्षक—की कड़ी सुरक्षा जांच, डिजिटल ट्रैकिंग और जवाबदेही तय होनी चाहिए। पेपर तैयार करने से लेकर वितरण तक ब्लॉकचेन या एआई आधारित एन्क्रिप्शन प्रणाली अपनाई जाए। लीक कराने, खरीदने या मध्यस्थता करने वालों के लिए न्यूनतम दस वर्ष की जेल, संपत्ति जब्ती और आजीवन परीक्षा प्रतिबंध जैसी कठोर सजाएं हों। सीबीआई या विशेष एजेंसी को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार मिले और फास्ट-ट्रैक अदालतों में मुकदमों का निपटारा सुनिश्चित किया जाए। साथ ही व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सख्त निगरानी और त्वरित कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। विकसित देशों में पेपर लीक जैसी घटनाएं अत्यंत दुर्लभ हैं क्योंकि उनकी परीक्षा प्रणाली पारदर्शी, तकनीकी रूप से मजबूत और जवाबदेह है। अमेरिका में एसएटी, एसीटी और एमसीएटी जैसी परीक्षाएं स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाती हैं। ये ज्यादातर कंप्यूटर आधारित होती हैं, जिसमें प्रश्न रैंडमाइज्ड होते हैं। चीटिंग को गंभीर नैतिक उल्लंघन माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय से निष्कासन या डिग्री रद्द हो सकती है। बड़े पैमाने के फ्रॉड में आपराधिक मुकदमा चलता है। यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में भी स्थिति बेहतर है। फ्रांस में बैकलॉरिएट परीक्षा में चीटिंग पर तीन वर्ष तक की जेल हो सकती है। ब्रिटेन की कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी परीक्षाओं में लीक की घटनाएं लगभग नहीं होतीं। जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया में परीक्षा संस्कृति इतनी मजबूत है कि लीक की संभावना ही नहीं रहती। चीन में गाओकाओ परीक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय मानकर चीटिंग पर सात वर्ष तक जेल और अन्य परीक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इन देशों में परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, मेटल डिटेक्टर और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग मानक हैं। मुख्य अंतर सिस्टम की मजबूती, भ्रष्टाचार नियंत्रण, तकनीकी उपयोग और सामाजिक मूल्यों में है, जहां मेरिट और कौशल को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। भारत में सुधार के लिए बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। पूरी परीक्षा प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाए, जिसमें प्रश्न बैंक से रैंडम प्रश्न चुने जाएं और हर छात्र को अलग सेट मिले। एनटीए जैसी संस्थाओं को स्वायत्त लेकिन सख्त जवाबदेही के दायरे में लाया जाए तथा स्वतंत्र बोर्ड द्वारा नियमित ऑडिट किया जाए। बड़े कोचिंग संस्थानों पर वित्तीय निगरानी और छापेमारी बढ़ाई जाए। स्कूल स्तर से नैतिक शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाएं। भारत एक युवा राष्ट्र है। यदि इन युवाओं का परीक्षा प्रणाली पर विश्वास टूट गया तो देश की विकास क्षमता प्रभावित होगी। निष्पक्ष परीक्षाएं ही प्रतिभा को सही दिशा दे सकती हैं और कौशल-आधारित समाज का निर्माण कर सकती हैं। सरकार को राजनीतिक लाभ से ऊपर उठकर इस मुद्दे को प्राथमिकता देनी चाहिए। विपक्ष, मीडिया, शिक्षाविद् और समाज सभी को मिलकर इस लड़ाई में योगदान देना होगा। यदि हम अभी सशक्त कानून नहीं बनाते, तकनीकी सुरक्षा नहीं अपनाते और सख्त कार्रवाई नहीं करते, तो भारत के बच्चों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ जारी रहेगा। एक मजबूत भारत के निर्माण के लिए निष्पक्ष और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली अनिवार्य है। तभी आने वाली पीढ़ियां सपनों को मेहनत से हासिल करने का विश्वास रख सकेंगी और राष्ट्र प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ सकेगा।

प्रेरणा

हंसते-हंसाते समाज की परतें खोलता तीखा व्यंग्य संसार

हिंदी साहित्य में व्यंग्य की परंपरा हमेशा से समाज की सच्चाइयों को उजागर करने का प्रभावशाली माध्यम रही है। व्यंग्यकार केवल हंसाने का काम नहीं करता, बल्कि वह समाज की उन विसंगतियों को सामने लाता है जिन्हें लोग सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसी परंपरा में सम्पत सरल का लेखन एक अलग पहचान रखता है। उनका व्यंग्य केवल मनोरंजन नहीं करता, बल्कि पाठक को भीतर तक झकझोर देता है। वे अपने अनूठे अंदाज में समाज, व्यवस्था और व्यक्ति की कमजोरियों को इस तरह सामने रखते हैं कि पाठक मुस्कुराते हुए भी अपनी वास्तविकता से सामना करने को मजबूर हो जाता है। सम्पत सरल की सबसे बड़ी ताकत उनकी पैनी दृष्टि है। वे उन छोटी-छोटी बातों में भी व्यंग्य खोज लेते हैं, जिन्हें सामान्यतः लोग महत्वहीन समझते हैं। सरकारी कार्यालयों की धीमी कार्यशैली, नेताओं के भाषण, सामाजिक दिखावा, आधुनिक जीवन की कृत्रिमता और आम आदमी की विडंबनाएं—सब कुछ उनकी रचनाओं का हिस्सा बन जाता है। वे किसी भी घटना को केवल घटना की तरह नहीं देखते, बल्कि उसके भीतर छिपी सामाजिक मानसिकता को पकड़ लेते हैं। यही कारण है कि उनके व्यंग्य पढ़ते समय पाठक को लगता है कि लेखक उसके अपने अनुभवों को शब्द दे रहा है। उनकी लेखनी की विशेषता यह है कि उसमें कृत्रिमता बिल्कुल नहीं है। वे कठिन शब्दों और भारी भाषा का सहारा नहीं लेते। उनकी भाषा सहज, बोलचाल वाली और सीधी है, लेकिन उसी सादगी में अद्भुत धार छिपी रहती है। वे बिना घुमावदार बातों के सीधे मुद्दे पर प्रहार करते हैं। यही वजह है कि उनका हर वाक्य प्रभाव छोड़ता है। उनकी रचनाओं में एक भी पंक्ति अनावश्यक नहीं लगती। वे शब्दों की फिजूलखर्ची नहीं करते, बल्कि कम शब्दों में गहरी चोट करने की कला जानते हैं। यही कसावट उनके व्यंग्य को प्रभावी बनाती है।

सम्पत सरल का मंचीय अनुभव भी उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। हास्य कवि और कथाकार होने के कारण उन्हें यह अच्छी तरह पता है कि श्रोता या पाठक की रुचि किस तरह बनाए रखनी है। उनके व्यंग्य में संवाद की सहजता और घटनाओं का नाटकीय प्रस्तुतिकरण दिखाई देता है। वे किसी साधारण परिस्थिति को भी इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि पाठक मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता। लेकिन उनकी मुस्कान केवल सतही नहीं होती। उसके पीछे समाज की एक गहरी सच्चाई छिपी होती है। यही सफल व्यंग्य की पहचान है कि वह हंसी के साथ विचार भी पैदा करे।

उनकी रचनाओं में व्यक्ति के व्यवहार का बहुत सूक्ष्म चित्रण मिलता है। वे उन लोगों पर तीखा कटाक्ष करते हैं जो अपने ज्ञान, पहनावे, भाषा या सामाजिक हैसियत का प्रदर्शन करने में लगे रहते हैं। आधुनिक समाज में दिखावे की जो संस्कृति बढ़ती जा रही है, सम्पत सरल उसे बड़ी बारीकी से पकड़ते हैं। चाहे कोई व्यक्ति अपनी टूटी-फूटी अंग्रेजी बोलकर खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहता हो, या फिर महंगे कपड़ों और बनावटी शिष्टाचार के जरिए अपनी अलग पहचान बनाना चाहता हो, सम्पत सरल उसकी वास्तविकता को तुरंत उजागर कर देते हैं। वे यह दिखाते हैं कि समाज में कई बार वास्तविकता से ज्यादा महत्व उसके प्रदर्शन को मिलने लगा है।

उनका व्यंग्य केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी व्यवस्था पर भी प्रहार करता है। सरकारी तंत्र की विसंगतियां, कर्मचारियों की लापरवाही और नियमों की हास्यास्पद जटिलता को उन्होंने बेहद प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। आम आदमी का सरकारी दफ्तरों में भटकना, छोटी-सी फाइल के लिए महीनों चक्कर लगाना और हर जगह नियमों के नाम पर परेशान होना—ये सब उनके व्यंग्य का हिस्सा बनते हैं। वे इन परिस्थितियों को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि पाठक हंसते-हंसते व्यवस्था की विफलताओं को समझने लगता है।

सम्पत सरल की खासियत यह भी है कि वे कटाक्ष करते समय कटुता पैदा नहीं होने देते। उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को अपमानित करना नहीं होता, बल्कि समाज की मानसिकता को सामने लाना होता है। यही कारण है कि उनके व्यंग्य में तीखापन होने के बावजूद सहजता बनी रहती है। वे समाज को आईना दिखाते हैं, लेकिन उस आईने में केवल दूसरों का चेहरा नहीं, बल्कि पाठक खुद को भी देखता है। यही वजह है कि उनकी रचनाएं केवल हंसी तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि आत्ममंथन का अवसर भी देती हैं।

उनके निबंधों में हास्य स्वतः उपस्थित रहता है। वे जब किसी घटना या चरित्र का वर्णन करते हैं तो उसमें इतनी स्वाभाविक चुटीलापन होता है कि पाठक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन यह हास्य फूहड़ता या बनावटीपन पर आधारित नहीं होता। उसमें बौद्धिक गहराई और सामाजिक चेतना दोनों मौजूद रहती हैं। यही कारण है कि उनकी रचनाएं पढ़ने के बाद केवल मनोरंजन का अनुभव नहीं होता, बल्कि समाज को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा भी मिलती है।

सम्पत सरल की रचनाओं का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वे आम आदमी के जीवन से जुड़ी होती हैं। वे किसी काल्पनिक दुनिया का निर्माण नहीं करते, बल्कि हमारे आसपास की वास्तविक घटनाओं को ही व्यंग्य का रूप देते हैं। यही कारण है कि पाठक उनकी हर बात से जुड़ाव महसूस करता है। उनके पात्र और परिस्थितियां इतनी परिचित लगती हैं कि लगता है जैसे लेखक हमारे ही समाज की कहानी लिख रहा हो। वे उन बातों को उजागर करते हैं जिन्हें लोग रोज देखते हैं, लेकिन उनके भीतर छिपी विडंबना को समझ नहीं पाते।

उनके 42 निबंधों का संग्रह अपने आप में सामाजिक जीवन का व्यंग्यात्मक दस्तावेज कहा जा सकता है। हर निबंध में अलग विषय, अलग परिस्थिति और अलग प्रकार का कटाक्ष दिखाई देता है। कहीं सामाजिक पाखंड पर प्रहार है, कहीं राजनीतिक ढोंग पर तंज है, तो कहीं आधुनिक जीवन की खोखली चमक पर तीखी टिप्पणी। इन निबंधों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे पाठक को बोझिल नहीं लगते। वे सहजता से पढ़े जाते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद देर तक मन में बने रहते हैं।

आज के समय में जब समाज तेजी से कृत्रिमता और दिखावे की ओर बढ़ रहा है, तब सम्पत सरल जैसे व्यंग्यकारों का महत्व और बढ़ जाता है। उनका लेखन हमें यह एहसास कराता है कि साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का सशक्त साधन भी है। वे हंसी के माध्यम से उन सवालों को उठाते हैं जिन पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। यही कारण है कि उनकी रचनाएं समय के साथ और अधिक प्रासंगिक होती जा रही हैं।

सम्पत सरल का व्यंग्य हमें यह सिखाता है कि हंसी केवल आनंद का विषय नहीं, बल्कि बदलाव का माध्यम भी हो सकती है। उनकी लेखनी में हास्य और गंभीरता का ऐसा संतुलन दिखाई देता है जो बहुत कम व्यंग्यकारों में देखने को मिलता है। वे पाठकों को हंसाते जरूर हैं, लेकिन साथ ही यह भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि समाज की जिन बातों पर हम हंस रहे हैं, वे वास्तव में हमारी सबसे बड़ी विडंबनाएं हैं।

मुख्यमंत्रियों के चुनाव हारने की परंपरा

सत्ताधारी मुख्यमंत्री का अपनी ही विधानसभा सीट गंवा देना भारतीय राजनीति का एक रोचक और जटिल पहलू है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक संदर्भों से लेकर हालिया चुनावी उथल-पुथल तक, यह सिलसिला लोकतंत्र की एक ऐसी गाथा सुनाता है जहां जनता की खामोशी सत्ता के अहंकार से कहीं अधिक शक्तिशाली सिद्ध होती है। भारतीय संसदीय इतिहास में मुख्यमंत्रियों के हारने की परंपरा पुरानी है, जो यह दर्शाती है कि यहां की लोकतांत्रिक जड़ें व्यक्ति विशेष के कद से हमेशा गहरी रही हैं। इसकी शुरुआत 1971 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह की मनीराम सीट पर हुई हार से हुई थी, जिसने देश को पहली बार यह अहसास कराया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी चुनावी जीत की गारंटी नहीं है। इसके बाद समय-समय पर बड़े नाम इस सूची में जुड़ते गए।

शिबू सोरेन का 2009 के उपचुनाव में तमाड़ सीट से हारना एक बड़े राजनीतिक संकट के रूप में उभरा, क्योंकि वह निर्वाचित हुए बिना मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे। इसी तरह बंगाल में 34 वर्षों के वामपंथी शासन के पतन की सबसे बड़ी मुहर मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की 2011 में जाधवपुर सीट पर हुई हार थी। उत्तराखंड की भूमि पर भी जनता ने बार-बार यह संदेश दिया है। 2012 में भुवन चंद्र खंडूड़ी का कोटद्वार से हारना और 2017 में हरीश रावत का हरिद्वार ग्रामीण एवं किच्छा जैसी दोनों सीटों से पराजित होना इसी लोकतांत्रिक चेतना का प्रतीक है। 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार से पराजित हुए, जबकि उनकी पार्टी भाजपा राज्य में स्पष्ट बहुमत के साथ वापसी कर रही थी। ये रुझान दर्शाते हैं कि सत्ता की चमक कभी भी मतदाता की मूल अपेक्षाओं और उसके स्वाभिमान के सामने टिक नहीं पाती।

किसी मुख्यमंत्री की हार के पीछे अक्सर सबसे बड़ा कारण उनका अति-आत्मविश्वास और सत्ता का अहंकार होता है। जब कोई नेता लंबे समय तक सत्ता में रहता है या भारी बहुमत से जीतता है तो अक्सर वह जनता की नब्ज टटोलने के बजाय अपनी इच्छाएं जनता पर थोपना शुरू कर देता है। जनता की भावनाओं को समझने के बजाय जब अपनी मनमानियों को जनमानस पर लादने की कोशिश करते हैं तो वहीं से उनके पतन की पटकथा लिखी जाती है। 2017 में हिमाचल के प्रेम कुमार धूमल की सुजानपुर में हार हो या गोवा के लक्ष्मीकांत पारसेकर की मंड्रेम में शिकस्त के पीछे जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और सत्ता का बढ़ता हुआ केंद्रीकरण था। जब जनता को यह लगने लगता है कि उनका सेवक अब उनका शासक बनने की कोशिश कर रहा है तो वह मतदान केंद्र पर चुपचाप अपनी ताकत दिखा देती है।

हाल के वर्षों में, विशेषकर 2021 से 2026 के मध्य, चुनाव में मुख्यमंत्रियों की हार के पैटर्न ने भारतीय राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। बंगाल के 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी से मात खा गईं। ममता बनर्जी ने उसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, लेकिन जनता ने यह संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष को अपनी जागीर नहीं समझ सकता। पंजाब में 2022 के चुनाव में चरणजीत सिंह चन्नी का अपनी दोनों सीटों, चमकौर साहिब और भदौड़ से हारना सत्ता के प्रति जनता के तीव्र मोहभंग का परिणाम था। 2024 में ओडिशा के अजेय माने जाने वाले नवीन पटनायक का कांटाबांजी सीट से हारना और 24 साल के शासन का अंत होना, इस बात का प्रमाण है कि जनता एक समय के बाद बदलाव और नई ऊर्जा चाहती है।

2026 के ताजा चुनावी परिणामों ने इस फेहरिस्त में सबसे चौंकाने वाले अध्याय जोड़े हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहते एमके स्टालिन का अपनी अभेद्य मानी जाने वाली कोलाथुर सीट पर एक नवोदित दल टीवीके के प्रत्याशी से लगभग 9,000 वोटों से हारना यह दर्शाता है कि दक्षिण की राजनीति में भी द्रविड़ किले में दरारें पड़ चुकी हैं। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट पर हार और सिक्किम में पवन कुमार चामलिंग की पूर्व में पराजय यह साबित करती हैं कि चेहरा कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह काम और व्यवहार का विकल्प नहीं हो सकता। कर्नाटक में सिद्दरमैया की चामुंडेश्वरी में हार भी इसी अहंकार की बलि चढ़ने का उदाहरण थी।

मुख्यमंत्रियों की हार को देखते हुए बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह निजी असफलता है या व्यापक राजनीतिक संकेत? वस्तुतः देखा जाए तो मुख्यमंत्रियों की हार के सवाल का उत्तर एक से अधिक आयामों में छिपा है। कई बार स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण, उम्मीदवार चयन में हुई चूक, गुटबाजी या विपक्षी उम्मीदवार की मजबूत अपील इसका कारण बनती है। यह राजनीतिक दलों के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि शीर्ष नेतृत्व की लोकप्रियता के भरोसे अकेले चुनाव नहीं जीते जा सकते। जमीनी संगठन, स्थानीय मुद्दों की समझ और उम्मीदवार की छवि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वहीं यह सत्ता विरोधी आक्रोश भी है, क्योंकि यह शासकों को चेतावनी देता है कि वे जनता की भावनाओं को हल्के में न लें। जब सत्ता के गलियारों में बैठे लोग जनता का मन टटोलना बंद कर देते हैं और अपनी नीतियां या अपनी सनक को उन पर थोपते हैं तो जनता का गुस्सा शांत, लेकिन प्रभावी ढंग से फूटता है।

अभियान

उगते सूरज की तस्वीर लगाने से पहले जान लें ये वास्तु रहस्य, तभी घर में आएगी सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा

भारतीय संस्कृति में सूर्य को केवल एक ग्रह या आकाशीय पिंड नहीं माना गया, बल्कि उसे जीवन, ऊर्जा, आत्मबल और सफलता का प्रतीक समझा गया है। सदियों से सूर्य देव की उपासना हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा रही है। यही कारण है कि वास्तु शास्त्र में भी सूर्य का विशेष महत्व बताया गया है। आजकल घरों को आकर्षक और आधुनिक बनाने के लिए लोग तरह-तरह की पेंटिंग, वॉल आर्ट और सजावटी तस्वीरें लगाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ तस्वीरें केवल सजावट के लिए नहीं होतीं, बल्कि उनका सीधा संबंध घर की ऊर्जा और वातावरण से भी माना जाता है। इन्हीं में से एक है उगते सूरज की तस्वीर।

वास्तु शास्त्र के अनुसार उगते सूरज की तस्वीर घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। यह नई शुरुआत, उम्मीद, सफलता और आत्मविश्वास का प्रतीक मानी जाती है। माना जाता है कि जिस घर में उगते सूरज की सही तस्वीर सही दिशा में लगाई जाती है, वहां रहने वाले लोगों के मन में उत्साह बना रहता है और परिवार में खुशहाली का वातावरण बना रहता है। लेकिन कई लोग केवल ट्रेंड या सजावट के लिए ऐसी तस्वीर खरीदकर कहीं भी लगा देते हैं। वास्तु के अनुसार यदि तस्वीर सही दिशा या सही स्थान पर न लगाई जाए, तो उसका शुभ प्रभाव कम हो सकता है या कभी-कभी उल्टा असर भी देखने को मिल सकता है।

वास्तु शास्त्र में सूर्य को पूर्व दिशा का स्वामी माना गया है। इसी कारण उगते सूरज की तस्वीर लगाने के लिए पूर्व दिशा सबसे उत्तम मानी जाती है। कहा जाता है कि पूर्व दिशा ज्ञान, ऊर्जा, स्वास्थ्य और तरक्की से जुड़ी होती है। जब इस दिशा में उगते सूरज की तस्वीर लगाई जाती है तो घर में सकारात्मक कंपन बढ़ते हैं और मानसिक शांति बनी रहती है। कई वास्तु विशेषज्ञ मानते हैं कि पूर्व दिशा में लगी ऐसी तस्वीर व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

अगर किसी घर में पूर्व दिशा में जगह उपलब्ध न हो, तो दक्षिण दिशा में भी उगते सूरज की तस्वीर लगाई जा सकती है। हालांकि इसके लिए तस्वीर का आकार, रंग और स्थिति संतुलित होना जरूरी माना गया है। दक्षिण दिशा में यह तस्वीर विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो करियर या व्यापार में प्रगति चाहते हैं। वहीं उत्तर और पश्चिम दिशा में उगते सूरज की तस्वीर लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार इन दिशाओं में ऐसी तस्वीर लगाने से उसका सकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है।

सिर्फ दिशा ही नहीं, बल्कि घर का कौन-सा हिस्सा इस तस्वीर के लिए चुना जाए, यह भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। उगते सूरज की तस्वीर ड्रॉइंग रूम, लिविंग एरिया, ऑफिस या हॉल में लगाना शुभ माना जाता है। यह घर में आने वाले मेहमानों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है और पूरे वातावरण को ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करती है। कई लोग अपने कार्यस्थल या ऑफिस के केबिन में भी ऐसी तस्वीर लगाते हैं ताकि काम में उत्साह और एकाग्रता बनी रहे।

हालांकि वास्तु शास्त्र में बेडरूम में उगते सूरज की तस्वीर लगाने की सलाह नहीं दी जाती, खासकर पति-पत्नी के कमरे में। माना जाता है कि सूर्य की तेज ऊर्जा विश्राम और शांति के वातावरण को प्रभावित कर सकती है। बेडरूम को आराम और मानसिक संतुलन का स्थान माना जाता है, इसलिए वहां हल्के और शांत वातावरण वाली तस्वीरें अधिक उपयुक्त मानी जाती हैं।

तस्वीर की गुणवत्ता और स्थिति का भी वास्तु में विशेष महत्व बताया गया है। घर में हमेशा साफ, स्पष्ट और अच्छी क्वालिटी वाली तस्वीर ही लगानी चाहिए। फटी हुई, धुंधली, टूटी या खराब फ्रेम वाली तस्वीरें नकारात्मक ऊर्जा का कारण मानी जाती हैं। यदि तस्वीर का रंग फीका पड़ जाए या उसमें दरार आ जाए, तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। वास्तु मान्यता के अनुसार खराब और टूटी हुई वस्तुएं घर के मानसिक वातावरण को प्रभावित करती हैं और धीरे-धीरे नकारात्मकता बढ़ा सकती हैं।

उगते सूरज की तस्वीर चुनते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सूरज स्पष्ट और चमकदार दिखाई दे। आसमान का रंग हल्का और सकारात्मक हो तथा तस्वीर में प्राकृतिक सौंदर्य झलकता हो। बहुत अधिक लाल, डरावनी या उदासी भरी तस्वीरें लगाने से बचना चाहिए। कई वास्तु विशेषज्ञ मानते हैं कि सात घोड़ों वाले उगते सूर्य की तस्वीर विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। यह सफलता, गति और निरंतर प्रगति का प्रतीक मानी जाती है। हालांकि ऐसी तस्वीर लगाते समय यह ध्यान देना जरूरी है कि घोड़ों के चेहरे स्पष्ट हों और वे सकारात्मक ऊर्जा का भाव प्रस्तुत कर रहे हों।

आजकल इंटीरियर डिजाइन के नाम पर लोग कई तरह की आधुनिक और कलात्मक तस्वीरें घर में लगा लेते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार हर तस्वीर का मानसिक प्रभाव होता है। इसलिए सजावट करते समय केवल सुंदरता नहीं, बल्कि उसके भाव और ऊर्जा को भी ध्यान में रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र में कुछ तस्वीरों को अशुभ माना गया है। इनमें डूबते सूरज की तस्वीर प्रमुख है। डूबता हुआ सूरज समाप्ति, निराशा और थकान का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी तस्वीरें घर के लोगों के मन में उदासी और नकारात्मक सोच बढ़ा सकती हैं।

इसी तरह युद्ध, हिंसा, रोते हुए बच्चों, अकेलेपन, सूखे पेड़, कांटेदार पौधों या उदासी दर्शाने वाली तस्वीरों को भी घर में लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। वास्तु मान्यता के अनुसार ऐसी तस्वीरें धीरे-धीरे मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकती हैं। कई बार लोग कला के नाम पर ऐसी पेंटिंग्स खरीद लेते हैं जिनका प्रभाव घर के वातावरण पर अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए सजावट के साथ-साथ भावनात्मक और मानसिक प्रभाव को समझना भी जरूरी है।

वास्तु शास्त्र का मूल उद्देश्य घर में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन बनाए रखना माना जाता है। हालांकि यह पूरी तरह व्यक्ति की आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है, लेकिन भारतीय समाज में वास्तु का प्रभाव लंबे समय से देखा जाता रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि सही दिशा और सही वातावरण जीवन में मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं। उगते सूरज की तस्वीर भी इसी सकारात्मक सोच और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है।

आधुनिक जीवन की भागदौड़ और तनाव के बीच लोग अपने घर को केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि मानसिक शांति का केंद्र बनाना चाहते हैं। ऐसे में घर की सजावट में इस्तेमाल होने वाली चीजें केवल दिखावे तक सीमित नहीं रह जातीं, बल्कि उनका संबंध भावनाओं और मानसिक स्थिति से भी जुड़ जाता है। उगते सूरज की तस्वीर लोगों को हर दिन नई शुरुआत और उम्मीद का संदेश देती है। सुबह का सूर्य यह याद दिलाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, उसके बाद उजाला जरूर आता है।

यही कारण है कि वास्तु में उगते सूरज को जीवन में प्रगति और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। लेकिन इसका पूरा लाभ तभी माना जाता है जब तस्वीर सही दिशा, सही स्थान और सही स्थिति में लगाई जाए। केवल फोटो लगाने से ही चमत्कार नहीं होता, बल्कि घर का वातावरण, लोगों का व्यवहार और सकारात्मक सोच भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। वास्तु शास्त्र भी अंततः संतुलन, स्वच्छता और सकारात्मकता पर ही जोर देता है।

इसलिए यदि आप अपने घर में उगते सूरज की तस्वीर लगाने की सोच रहे हैं, तो केवल उसकी सुंदरता देखकर निर्णय न लें। उसकी दिशा, स्थान, गुणवत्ता और भाव को भी ध्यान में रखें। सही तरीके से लगाई गई ऐसी तस्वीर घर के वातावरण को ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता से भर सकती है, जबकि गलत तरीके से लगाई गई तस्वीर अपना शुभ प्रभाव खो सकती है। भारतीय परंपरा में सूर्य को जीवनदाता माना गया है और शायद यही वजह है कि घर में उगते सूरज की तस्वीर केवल सजावट नहीं, बल्कि आशा और नई शुरुआत का प्रतीक बन जाती है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई गुजरात की अविरत विकास यात्रा को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की सरकार कुशलतापूर्वक आगे बढ़ा रही है : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

- स्थानीय निकाय-पंचायत चुनावों में विजय जनता का विकास पर भरोसा
- आधुनिक तथा सुविधाजनक शहर बनने के साथ गांधीनगर सबसे सुंदर लोकसभा क्षेत्र बना

.....

- **शहरों को बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा ग्रीन एन्वायर्नमेंट के साथ पॉपुलेशन फ्री, गार्बेज फ्री एवं स्लम फ्री बनाने का सरकार का संकल्प है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल**

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- छोटे शहरों तथा उनके आसपास के क्षेत्रों को 'सिटी इकोनॉमिक रीजन' के रूप में विकसित किया जा रहा है
- गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को सर्वाधिक हरियाला बनाने का सांसद श्री अमित शाह ने सुदृढ़ आयोजन किया है
- गांधीनगर संसदीय क्षेत्र को देश का सर्वाधिक विकसित संसदीय क्षेत्र बनाने का श्री अमित शाह का लक्ष्य
- **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के करकमलों से गांधीनगर महानगर पालिका के कुल 620 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का ई-लोकार्पण-शिलान्यास किया गया**

गांधीनगरः केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने रविवार को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में गांधीनगर महानगर पालिका के कुल 620 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का ई-लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गुजरात में शुरू की गई अविरत विकास यात्रा को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की सरकार अत्यंत कुशलतापूर्वक आगे बढ़ा रही है। गांधीनगर महानगर पालिका (जीएमसी) द्वारा शुरू किए गए कार्यों में पेथापुर जैसे क्षेत्रों में पेयजल सुविधा, पुस्तकालय, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सीमेंट रोड जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। श्री शाह ने गुजरात सरकार तथा गांधीनगर मनपा के कामकाज की प्रशंसा करते हुए कहा कि गांधीनगर मनपा तथा राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से शहर के नागरिकों की सुख-सुविधा के लिए सीवेज के पानी के शुद्धिकरण, तालाबों के सौंदर्यीकरण, नर्मदा का शुद्ध जल घर-घर पहुंचाने तथा योग केंद्रों जैसी आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया है।

अहंकार नहीं, आत्मविश्वास हमारी सरकार की पहचान है। यह कहते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना काल के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की चिंता किए बिना लोगों की सेवा की है। फूड किट पहुंचाने से लेकर वैक्सीनेशन की व्यवस्था तक के कामकाज ने जनता में पार्टी के प्रति अटूट विश्वास जगाया है। हाल के स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनाव परिणामों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में भाजपा की विजय जनता का विकास पर भरोसा है।

उन्होंने पश्चिम बंगाल की स्थिति तथा विकास की तुलना करते हुए कहा कि आज देश में 80 प्रतिशत क्षेत्र में भाजपा तथा एनडीए की सरकार है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में एनडीए सरकार बनी

है, जो कार्यकर्ताओं की तपस्या तथा परिश्रम का परिणाम है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने गांधीनगर को एक आधुनिक एवं सुविधाजनक शहर बनाने तथा सबसे सुंदर व सुविधायुक्त संसदीय क्षेत्र बनाने की कटिबद्धता व्यक्त की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रसंगोचित संबोधन में कहा कि शहरों को डेवलपमेंट प्लानिंग में बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ ग्रीन एन्वायर्नमेंट वाले पॉलुशन फ्री, गार्बेज फ्री तथा स्लम फ्री सिटी बनाने का राज्य सरकार का संकल्प है।

उन्होंने उल्लेख किया कि इस संकल्प व विजन के अनुरूप अब छोटे शहरों तथा उनके आसपास के क्षेत्रों को 'सिटी इकोनॉमिक रीजन' के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में श्री अमित शाह ने लॉन्ग टर्म तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा अपनाकर गांधीनगर संसदीय क्षेत्र को सर्वाधिक हरियाला संसदीय क्षेत्र बनाने का सुदृढ़ आयोजन किया है। इसमें ग्रीन सिटी की पहचान रखने वाले गांधीनगर के महानगर पालिका क्षेत्र में इस वर्ष पांच लाख पेड़-पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकास की राजनीति से विकास कार्यों का आमूलचूल कायाकल्प किया है और शहरी विकास की गति को बढ़ाया है। एक समय नगर पालिका-महानगर पालिका क्षेत्र के पूरे वर्ष के बजट की जो बजट राशि थी, आज उतनी राशि के विकास कार्य एक ही दिन में होते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा सांसद श्री अमित शाह की जोड़ी ने सुराज्य-गुड गवर्नेंस की लोगों को प्रत्यक्ष अनुभूति कराई है। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि श्री अमित शाह जब-जब अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं, तब-तब लोगों के ईज ऑफ लिविंग में वृद्धि करने वाले अनेक विकास कार्यों की भेंट देते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस विजन के अनुरूप तथा आदरणीय श्री अमित शाह के संसदीय क्षेत्र में शामिल सरखेज-धोलेरा सेमीहाईस्पीड रेल लाइन के लिए 20 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। उन्होंने इसके लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अमित शाह ने गांधीनगर संसदीय क्षेत्र को सर्वाधिक विकसित संसदीय क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके हिस्से के रूप में आज श्री शाह ने महानगर पालिका तथा जनता को गांधीनगर में नए विकसित हो रहे क्षेत्रों सहित राजधानी को ड्रैनेज, पंपिंग स्टेशन, लेक ब्यूटीफिकेशन, लाइब्रेरी, रोड डेवलपमेंट, हेल्थ सेंटर जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के 26 कार्यों के शिलान्यास तथा 21 कार्यों के लोकार्पण के 620 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की भेंट दी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्तमान वैश्विक स्थिति में आत्मनिर्भर भारत के लिए देशवासियों से नागरिक दायित्व के हिस्से के रूप में जो अपील की गई है, उसका पालन करते हुए आगे बढ़ने का सबसे अनुरोध किया।

गांधीनगर की महापौर श्री मीराबेन पटेल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा तथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और गांधीनगर के लोकप्रिय सांसद श्री अमितभाई शाह के मार्गदर्शन में गांधीनगर शहरी विकास के नए मानदंड स्थापित कर रहा है। उन्होंने जोड़ा कि महानगर पालिका 'विकसित भारत-2047' और 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को सार्थक करने तथा नागरिकों की सुख-सुविधा के लिए सतत कार्यरत है। महापौर ने कहा कि इन विकास कार्यों के अंतर्गत शहर में पर्यावरण संरक्षण के लिए गार्डन डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या निवारण के लिए ओवरहेड टंकी एवं वितरण नेटवर्क, नजदीक में ही चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए अर्बन हेल्थ सेंटर्स तथा नए वॉर्ड ऑफिस जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री की सार्वजनिक जीवन में मितव्ययिता-बचत तथा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील को स्वीकार कर मनपा ने कम लागत से श्रेष्ठ एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का संकल्प किया है।

अंत में, उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया कि वे गांधीनगर को देश की सबसे स्वच्छ, स्मार्ट, सुरक्षित एवं सर्वांगीण सक्षम राजधानी बनाने के लिए इस विकास यज्ञ में सहभागी हों।

विधायक श्री रीटाबेन पटेल ने स्वागत संबोधन के साथ गांधीनगर की विकास यात्रा की तीव्र गति का वर्णन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने गुजरात की विकास यात्रा का प्रारंभ कराया, जिसे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी आगे बढ़ा रहे हैं। गांधीनगर शिक्षा क्षेत्र में हब के रूप में उभर आया है। आज नए जुड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्र में सिविल अस्पताल, पीएचसी सहित पर्यावरण से लेकर जल प्रबंधन, सीवेज व्यवस्था जैसी अंतरढांचागत सुविधाओं का भी निर्माण हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री के करकमलों से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इनमें जनता की स्वास्थ्य सुख-सुविधा के लिए सेक्टर 21, 22 तथा सरगासण में नवनिर्मित अर्बन हेल्थ सेंटर्स, सेक्टर 25 व सरगासण में आधुनिक योग स्टूडियो तथा भाट एवं झुंडाल में पीएचसी सेंटर्स का लोकार्पण, पेथापुर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति वितरण नेटवर्क से युक्त 2 नई ओवरहेड टंकी, रांधेजा में जीएमसी वॉर्ड कार्यालय तथा शॉपिंग सेंटर, अमियापुर में भव्य कम्युनिटी हॉल और सेक्टर 1 में रमणीय गार्डन विकास, नागरिकों की सुविधा के लिए महानगर पालिका द्वारा बेकहो लोडर, इमर्जेंसी रेस्क्यू वाहन, होपर टिपर डम्पर, मिनी यूएचपी मशीनों तथा वॉटर ब्राउजर सुविधाओं जैसे विभिन्न प्रकार के कुल 37 अत्याधुनिक वाहन, उपकरण एवं सुविधा जनता की सेवा में आज से कार्यरत होंगे, जबकि नागरिकों की भावी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दूरगामी प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया। इनमें 135 करोड़ रुपए की लागत से जासपुर में 100 एमएलडी क्षमता वाला आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), नया टर्मिनल पंपिंग स्टेशन, पेथापुर में अद्यतन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, योग सेंटर तथा डिजिटल लाइब्रेरी, कोबा व पेथापुर में नए कम्युनिटी हॉल का निर्माण, रक्षाशक्ति फ्लाईओवर से धोळेश्वर महादेव ब्रिज तक गांधीनगर बाईपास रोड और कोबा सर्किल से पंचेश्वर सर्किल तक रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सेक्टर 27 स्थित गायत्रीनगर के उद्यान का नवीनीकरण, सेक्टर 25 स्थित तालाब का सौंदर्यीकरण और कुडासण, रायसण एवं सरगासण आदि विभिन्न टीपी क्षेत्रों में नए आंतरिक मार्गों के निर्माण की प्रक्रिया वेगवान बनेगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से 'कल्पसर परियोजना' को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। नीदरलैंड के अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री श्री रॉब जेटेन के साथ नीदरलैंड की प्रसिद्ध जल प्रबंधन संरचना, 'अफस्लुइटडिज्क' (Afsluitdijk) का दौरा किया। उन्होंने इस बांध में इस्तेमाल की गई तकनीक को सीखने योग्य बताया। उल्लेखनीय बात यह है कि 'अफस्लुइटडिज्क' और गुजरात की कल्पसर परियोजना के बीच बहुत-सी समानताएं हैं। कल्पसर परियोजना पर तकनीकी सहयोग के लिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भारत के जल शक्ति मंत्रालय और नीदरलैंड के बुनियादी ढांचा और जल प्रबंधन मंत्रालय के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इससे परियोजना का कार्य तेज रफ्तार से आगे बढ़ने के नए द्वार खुल गए हैं।

अनियमित वर्षा और सूखे की समस्या से वर्षों से जूझ रहे गुजरात को सरदार सरोवर बांध के निर्माण से राहत तो मिली है, लेकिन दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी एक परियोजना पर ही निर्भर रहना जोखिम ही कहा जा सकता है। इसीलिए, तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने खंभात की खाड़ी में महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना की संकल्पना की थी। हालांकि, यह परियोजना तकनीकी रूप से अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण है।

क्या है कल्पसर परियोजना

कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी में एक विशाल बांध का निर्माण कर समुद्र में गिर रहीं सात नदियों के पानी का उपयोग करने की योजना है। इस योजना का उद्देश्य खंभात की खाड़ी पर मीठे पानी का एक विशाल जलाशय बनाना है, जिसमें ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन, सिंचाई और परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर का एकीकृत विकास शामिल है।

वर्ष 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से कल्पसर बांध की पथरेखा सुनिश्चित करने के लिए भावनगर में समुद्री सर्वेक्षण का ऐतिहासिक शुभारंभ किया गया। लेकिन, योजना के बेहद जटिल होने के कारण इसे साकार करने में कई प्रकार की मुश्किलें सामने आ रही हैं। इन मुश्किलों से निपटने के लिए सरकार की ओर से लगातार ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में, 30 मार्च, 2026 को गांधीनगर में नीदरलैंड की राजदूत सुश्री मारिसा गेराड्र्स से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कल्पसर योजना को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की और 'इंडो-डच' विशेषज्ञ समूह के गठन और जी2जी भागीदारी के बारे में चर्चा की।

कल्पसर परियोजना से मिलेंगे ये लाभ

कल्पसर परियोजना के साकार होने पर सौराष्ट्र के 9 जिलों की 42 तहसीलों को लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलेगा। इस योजना से दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के बीच की दूरी 240 किलोमीटर से कम होकर 60 किलोमीटर रह जाएगी। इतना ही नहीं, योजना से लगभग 1500 मेगावाट पवन ऊर्जा और 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। योजना से पर्यटन और मत्स्य पालन का विकास भी सुनिश्चित होगा।

जनगणना 2027 अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी स्व-गणना ऑनलाइन माध्यम से पूर्ण करके जनगणना 2027 की स्व-गणना का औपचारिक शुभारंभ कराया

- **राज्य के नागरिकों से आज से 31 मई 2026 तक निर्धारित 15 दिनों में स्व-गणना करके महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का अनुरोध किया गया**
- 2027 की जनगणना में पहली बार शुरू की गई स्व-गणना पद्धति के तहत ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल के माध्यम से जानकारी दी जा सकेगी

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जनगणना 2027 के अंतर्गत रविवार से शुरू हुई स्व-गणना का राज्यव्यापी शुभारंभ कराया। 31 मई 2026 तक निर्धारित 15 दिनों में लोग अपनी आवश्यक जानकारी स्वयं ऑनलाइन भरकर इस प्रक्रिया में सहभागी बन सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अपने परिवार की जानकारी जनगणना प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन भरकर स्व-जनगणना की औपचारिक शुरुआत कराई।

उन्होंने राज्य के नागरिकों से भी इस राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेकर सशक्त, समावेशी और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का अनुरोध किया।

उल्लेखनीय है कि इस बार जनगणना 2027 पूरी तरह डिजिटल माध्यम से पोर्टल और मोबाइल आधारित की जा रही है।

स्व-गणना की यह पहल नागरिकों को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है, जिसके माध्यम से नागरिक कहीं से भी अपनी जानकारी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

नागरिक https://se.census.gov.in/ के माध्यम से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर अपनी स्व-गणना पूरी कर सकते हैं तथा सक्रिय नागरिक भागीदारी के जरिए अपनी जानकारी ऑनलाइन भरकर समय पर और सटीक सूचना भी दे सकते हैं।

जनगणना 2027 में पहली बार स्व-गणना पद्धति प्रस्तुत की जा रही है। गुजरात में यह गणना 17 से 31 मई 2026 के दौरान वेब पोर्टल पर नागरिकों द्वारा अपनी जानकारी प्रदान कर स्व-गणना में भाग लेने के माध्यम से की जाएगी।

इसके बाद 1 से 30 जून 2026 के दौरान 1 लाख से अधिक जनगणना कार्यकर्ताओं द्वारा हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (एचएलओ) संचालित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी जानकारी स्व-गणना के अंतर्गत भरने के समय राज्य के जनगणना संचालन निदेशक श्री सुजल मयात्रा ने उन्हें स्मृति चिह्न भेंट कर जनगणना संबंधी गतिविधियों की जानकारी दी।

रेल सुरक्षा बल,अहमदाबाद मंडल द्वारा सराहनीय कार्य,महिला यात्री का खोया कीमती सामान लौटाया एवं लापता बालक को सुरक्षित संरक्षण प्रदान किया

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में रेल सुरक्षा बल (RPF) द्वारा यात्रियों की सुरक्षा एवं सहायता हेतु निरंतर सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक 16 मई 2026 को RPF अहमदाबाद मंडल द्वारा दो महत्वपूर्ण मामलों में तत्परता एवं मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया गया।

RPF ने आभूषणों से भरा पर्स सुरक्षित लौटाया गया

प्रथम घटना में रेल मदद पर शिकायत प्राप्त हुई कि गाड़ी संख्या 22962 वंदे भारत एक्सप्रेस में कोच संख्या C-8 की सीट संख्या 53 पर एक महिला यात्री का लेडीज पर्स छूट गया है। शिकायतकर्ता की पत्नी सूरत स्टेशन पर उतर चुकी थीं। शिकायत प्राप्त होते ही ASI छगनलाल एवं कांस्टेबल समरपाल ने तुरंत संबंधित कोच को अटेंड किया और सीट संख्या 53 पर एक भूरे रंग का लेडीज पर्स बरामद किया। उपस्थित यात्रियों के समक्ष पर्स की जांच करने पर उसमें 4300 नगद, एक डेबिट कार्ड एवं सोने के आभूषण पाए गए। शिकायतकर्ता की पत्नी श्रीमती श्वेता से मोबाइल पर संपर्क कर पर्स का सत्यापन कराया गया। बाद में गाड़ी संख्या 22961 वंदे भारत एक्सप्रेस के सूरत स्टेशन पहुंचने पर शाम 6:50 बजे यात्री को उनका पर्स सुरक्षित एवं सही-सलामत सुपुर्द किया गया।

पर्स में कुल लगभग 3,01,300 मूल्य का सामान था, जिसमें सोने का मंगलसूत्र, चैन, कान की बाली, अंगूठियां, ब्रेसलेट, ईयरबड्स एवं नगद राशि शामिल थी। यात्री एवं उनके परिजनों ने RPF की तत्परता एवं ईमानदारी की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

लापता बालक को मिला सुरक्षित संरक्षण

दूसरी घटना में अहमदाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर एक लापता बालक को सुरक्षित संरक्षण प्रदान किया गया। मुंबई के डी.बी. मार्ग थाना में BNS-2023 की धारा 137(2) के अंतर्गत दर्ज प्रकरण के संबंध में निरीक्षक अहमदाबाद द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर आरपीएफ़ स्टाफ द्वारा खोजबीन की गई। इस दौरान LHC हेतल सोनी को प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर मणिनगर साइड एक बालक दिखाई दिया, जिसकी पहचान प्राप्त फोटो से मिलान करने पर वही बालक होना पाई गई। सूचना मिलने पर ऑन ड्यूटी सेक्टर इंचार्ज ASI अरुण सिंह द्वारा बालक को RPF पोस्ट अहमदाबाद लाकर पूछताछ की गई। तत्पश्चात संबंधित प्रकरण के जांच अधिकारी PSI घनश्याम दरेकर, मुंबई से संपर्क स्थापित किया गया। आवश्यक कागजी कार्रवाई के उपरांत बालक को प्रयास जुवेनाइल सहायता केंद्र सोसायटी, सरसपुर के अधीक्षक को सुरक्षित सुपुर्द किया गया।

सहकार से समृद्धि की ओर दृढ़ कदम

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के करकमलों से गांधीनगर के दशेला में मधुर डेयरी के अनुमानित 128 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का लोकार्पण

- **डेयरी सेक्टर में 'सर्कुलर इकोनॉमी' को लागू कर पशुपालकों की आय में 20 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य : केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह**

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

- मधुर डेयरी का नया प्लांट पशुपालकों की आर्थिक उन्नति का आधार बनेगा, 75 प्रतिशत मुनाफा सीधे ही पशुपालकों के बैंक खातों में जमा होगा
- गुजरात में 36 लाख पशुपालक बहनें प्रतिदिन 200 करोड़ रुपए की आय प्राप्त कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती हैं
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'श्वेत क्रांति – 2.0' विजन अंतर्गत आगामी 10 वर्ष में देश में दूध उत्पादन तीन गुना करने का लक्ष्य
- **गुजरात की धरती सदियों से सहकारिता की भावना से समृद्ध धरती है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल**
- **प्रधानमंत्री ने बदलते परिप्रेक्ष्यों के साथ सहकारिता क्षेत्र भी कदम से कदम मिला सके; ऐसे विजन से 'सहकार से समृद्धि' का मार्ग अपनाया है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल**
- **गुजरात विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी, उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी तथा सहकारिता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी सहित महानुभावों की प्रेरक उपस्थिति**

गांधीनगर : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के करकमलों से रविवार को गांधीनगर के दशेला में मधुर डेयरी के नवनिर्मित मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी, उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, सहकारिता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री जगदीशभाई विश्वकर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर पशुपालक बहनों ने केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का स्वागत भी किया।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दशेला में 15 एकड़ भूमि में 128 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित यह पूर्णतः ऑटोमैटिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट पशुपालकों की आर्थिक उन्नति का आधार बनेगा। यह प्लांट दैनिक ढाई लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग करेगा, जिसे भविष्य में पांच लाख लीटर तक बढ़ाने की योजना है। इस प्लांट के संचालन खर्च के बाद होने वाला लगभग 75 प्रतिशत मुनाफा सीधे ही पशुपालकों के बैंक खातों में जमा होगा।

डेयरी सेक्टर को महिला सशक्तिकरण का विशेष माध्यम बताते हुए श्री शाह ने जोड़ा कि आज गुजरात में 36 लाख पशुपालक बहनों के माध्यम से दैनिक तीन करोड़ लीटर दूध एकत्र किया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रतिदिन लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि सीधे बहनों के बैंक खातों में जमा होती है। उन्होंने निजी अनुभव का वर्णन करते हुए कहा कि पहले जो बहनें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं थीं, वे आज डेयरी सेक्टर के कारण 'घर की सेठ' बनी हैं। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि डेयरी सेक्टर में 'सर्कुलर इकोनॉमी' को प्रोत्साहन देकर पशुपालकों की आय में कम से कम 20 प्रतिशत की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने अमूल के उत्पादों के प्रति लोगों में बढ़ रहे विश्वास का उदाहरण देते हुए कहा कि अमूल की शुगर फ्री चॉकलेट 'शुगर फ्री चॉकलेट' कैटेगरी में देश में पहले स्थान पर है, जिसका सीधा फायदा किसानों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि श्वेत क्रांति 2.0 अंतर्गत आगामी 10 वर्ष में देश का कुल दूध उत्पादन तीन गुना बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अमूल ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से पशुपालकों का मुनाफा बढ़ाने का कार्य किया है। श्री शाह ने हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल सहायक 'सरलाबेन' का उल्लेख किया, जो आज ग्रामीण क्षेत्र की बहनों को पशुपालन एवं खेती में सहायक हो रही है। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने मधुर डेयरी की प्रगति की प्रशंसा करते हुए कहा कि मधुर डेयरी सरदार वल्लभभाई पटेल, त्रिभुवनभाई पटेल तथा डॉ. वर्गीस कुरियन की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। मधुर डेयरी द्वारा वर्ष 1971 में केवल 4 मंडलियों तथा 6000 लीटर दूध एकत्रीकरण से शुरू की गई यात्रा आज 268 करोड़ रुपए के वार्षिक टर्नओवर तक पहुंची है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मधुर डेयरी के मिल्क प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग प्लांट के लोकार्पण अवसर पर कहा कि गुजरात की धरती सदियों से सहकारिता की भावना से समृद्ध धरती है। श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बदलते जा रहे परिप्रेक्ष्यों के साथ सहकारिता क्षेत्र भी कदम से कदम मिलाकर चल सके; ऐसे विजन के साथ 'सहकार से समृद्धि' का मार्ग अपनाया है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने विकास की राजनीति का नया इतिहास रचा है, उसमें भी सबके सहयोग से देश की समृद्धि का ही भाव हृदय में रखा है, जिसके फलस्वरूप उन्होंने जनता-जनार्दन का अपार विश्वास तथा भरोसा प्राप्त किया है।

मुख्यमंत्री ने मधुर डेयरी के ऐतिहासिक संस्मरणों को ताजा करते हुए कहा कि आज से साढ़े पांच दशक पहले केवल तीन-चार दूध उत्पादक सहकारी मंडलियों ने यह संघ शुरू किया था और अब गांधीनगरवासियों की हर सुबह मधुर ब्रैंड नेम के दूध की चाय से ही होती है।

उन्होंने मधुर डेयरी तथा गांधीनगर जिला दूध उत्पादक संघ की अन्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि गांधीनगर में दूध का उपभोग करने वालों यानी दूध उपभोक्ताओं की सहकारी मंडली पचास वर्ष से कार्यरत है। 15 हजार सभासदों वाली यह मंडली 230 वितरण केंद्रों से मधुर डेयरी के दूध का वितरण करती हैं।

मुख्यमंत्री ने मधुर डेयरी के इस कार्यक्रम को श्री अमितभाई के दिशादर्शन में गांधीनगर में श्वेत क्रांति से विकास क्रांति का उत्सव बताया और डेयरी की विकास गाथा में नया सोपान जुड़ने के लिए मधुर डेयरी परिवार को अभिनंदन दिया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मंच से केंद्रीय मंत्री श्री अमितभाई शाह को पश्चिम बंगाल चुनाव की विजय का श्रेय देते हुए उनका अभिवादन किया। श्री भूपेंद्र पटेल ने जोड़ा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व को प्रचंड समर्थन दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अमित शाह ने संगठन शक्ति, कार्यकर्ता आधारित राजनीति तथा जन विश्वास किस तरह जीता जा सकता है, उसका जीवंत उदाहरण पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों के जरिये दिखाया है। श्री पटेल ने इसकी प्रशंसा की।

कार्यक्रम के प्रारंभ में मधुर डेयरी के चेयरमैन श्री शंकरसिंह राणा ने सभी का स्वागत करते हुए मधुर डेयरी की विस्तृत पृष्ठभूमि प्रस्तुत की।

इस अवसर पर अमूल फेडरेशन-जीसीएमएमएफ के चेयरमैन श्री अशोकभाई चौधरी, नाफेड के चेयरमैन श्री जेठाभाई आहिर, गांधीनगर दक्षिण के विधायक श्री अल्पेश ठाकोर, मेहसाणा के विधायक श्री जे. एस. पटेल, दहेगाम के विधायक श्री बलराजसिंह चौहाण, सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरुणकुमार सोलंकी, मधुर डेयरी के निदेशक मंडल के सदस्य, सहकारिता अग्रणी सहित बड़ी संख्या में पशुपालक एवं किसान उपस्थित रहे।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के करकमलों से अहमदाबाद में 'मिलियन माइंड्स टेक पार्क' और 'गणेश रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट' का लोकार्पण किया गया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की प्रेरक उपस्थिति

जिस प्रकार गुजरात ने आजादी के समय से देश का नेतृत्व किया है, उसी प्रकार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी गुजरात देश का नेतृत्व करेगा : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

गुजरात अब टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और नॉलेज आधारित अर्थव्यवस्था का वैश्विक केंद्र बनेगा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के करकमलों से रविवार को अहमदाबाद में 'मिलियन माइंड्स टेक पार्क' तथा 'गणेश रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट' का लोकार्पण किया गया।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि जिस प्रकार गुजरात ने आजादी के समय से देश का नेतृत्व किया है, उसी प्रकार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी गुजरात देश का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि गुजरातियों के डीएनए में विकास है। आज लोकार्पित किए गए ये दोनों प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गुजरात को मैन्युफैक्चरिंग हब से आगे बढ़ाकर वैश्विक सेवा और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के विजन को नई दिशा देंगे।

उन्होंने गुजरात को सर्विस सेक्टर में टॉप श्री में लाने की मंशा व्यक्त करते हुए कहा कि गुजरात ने आर्थिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया है। 'मिलियन माइंड्स टेक पार्क' के माध्यम से राज्य में हजारों युवाओं के लिए उच्च कौशल आधारित रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस टेक पार्क में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर सहित अत्याधुनिक क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार और टेक्नोलॉजी विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य

में वैश्विक स्तर की टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम विकसित करने में यह प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण साबित होगा।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि 'गणेश रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट' रियल एस्टेट क्षेत्र में व्यावसायिकता और आधुनिकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संस्थान में आधुनिक अर्बन प्लानिंग, टेक्नोलॉजी आधारित पाठ्यक्रम तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण के माध्यम से कुशल मानव संसाधन तैयार किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि गुजरात आज टेक्नोलॉजी, उद्योग और आधुनिक बुनियादी ढांचा विकास के क्षेत्र में देश को नई दिशा दे रहा है। ऐसी विशिष्ट संस्थाएं और टेक्नोलॉजी आधारित प्रोजेक्ट्स राज्य को वैश्विक अर्थव्यवस्था में और अधिक मजबूत स्थान दिलाने में सहायक बनेंगे।

उन्होंने कहा कि वैष्णोदेवी सर्कल के निकट अहमदाबाद-गिफ्ट सिटी-गांधीनगर हाई ग्रोथ कॉरिडोर में लगभग 65 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही इस टेक सिटी में ग्रेड-ए ऑफिस स्पेस, आवासीय सुविधाएं, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल किया गया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 70 हजार से अधिक उच्च कौशल आधारित रोजगार का सृजन होगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गुजरात ने विकास की राजनीति को राष्ट्रीय विचारधारा में परिवर्तित किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात ने मैन्युफैक्चरिंग, पोर्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, फार्मा और निवेश के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। अब राज्य विकास के नए चरण में आईटी, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आधारित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'मिलियन माइंड्स टेक पार्क' गुजरात के टेक्नोलॉजी आधारित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह प्रकल्प केवल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि हाई स्किल रोजगार सृजन और डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देने वाला केंद्र बनेगा। प्रोजेक्ट के पहले चरण में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा।

उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और नॉलेज बेस्ड सर्विसेस के क्षेत्र में गुजरात 2.0 का सपना साकार हो रहा है। राज्य सरकार की आईटी पॉलिसी तथा जीसीसी पॉलिसी और केंद्र सरकार की प्रोत्साहक नीतियों के कारण गुजरात में आईटी सेक्टर का तेजी से विकास होगा।

उन्होंने कहा कि गिफ्ट सिटी आज वैश्विक वित्तीय और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के रूप में विकसित हो रही है, जबकि साणंद और धोलेरा एसआईआर क्षेत्र में विकसित हो रही सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम गुजरात को सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करेगी। गिफ्ट सिटी और धोलेरा आने वाले समय में गुजरात के आर्थिक विकास के शक्तिशाली इंजन बनेंगे।

मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद-धोलेरा के बीच लगभग 20 हजार करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली देश की पहली सेमी हाईस्पीड रेल परियोजना को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर देश-विदेश के निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

उन्होंने कहा कि अहमदाबाद आज मेट्रो, रिवरफ्रंट, एक्सप्रेस-वे, आधुनिक शहरी सुविधाओं और मजबूत कनेक्टिविटी के साथ देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में शामिल हो चुका है। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण अहमदाबाद वैश्विक शहर के रूप में उभर रहा है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया ने 'विकसित भारत 2047' के संकल्प को साकार करने में गुजरात महत्वपूर्ण योगदान देगा और इस आधुनिक प्रकल्प के लिए गणेश ग्रुप के चेयरमैन श्री दीपकभाई पटेल तथा एमडी श्री शेखरभाई पटेल को बधाई दी।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

इस कार्यक्रम में आयोजित पैनल डिस्कशन में उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि आने वाला समय गुजरात का है और देश-विदेश से आने वाले निवेशकों तथा उद्योगों के लिए गुजरात पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि गिफ्ट सिटी आने वाले समय में वैश्विक स्तर की कई बड़ी कंपनियों का केंद्र बनने जा रही है। गुजरात आज केवल औद्योगिक विकास में ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, वित्तीय सेवाओं और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

इस अवसर पर गणेश हाउसिंग लिमिटेड के अध्यक्ष श्री दीपकभाई पटेल, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री शेखर पटेल, श्री अनमोल पटेल सहित कई उद्योगपति तथा अग्रणी उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे ने मोटरमैन एवं ट्रेन मैनेजरों के कल्याण,विश्राम एवं स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

पश्चिम रेलवे अपने फ्रंट लाइन के कर्मचारियों, विशेष रूप से मोटरमैन एवं ट्रेन मैनेजरों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ एवं अनुकूल कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ये कर्मचारी मुंबई की उपनगरीय रेल सेवाओं के सुरक्षित, संरक्षित एवं समयनिष्ठ संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कर्मचारियों के कल्याण एवं स्वास्थ्य के प्रति पश्चिम रेलवे की निरंतर प्रतिबद्धता के अनुरूप, मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा विश्राम सुविधाओं, कल्याणकारी उपायों, काउंसलिंग सहायता, चिकित्सा जागरूकता कार्यक्रमों तथा क्रू सदस्यों एवं उनके परिवारों के साथ नियमित संवाद की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था स्थापित की गई है।

चर्चगेट, बोरीवली एवं विरार स्टेशनों पर पूर्णतः वातानुकूलित एकीकृत क्रू लॉबी उपलब्ध कराई गई हैं। इन लॉबी में एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन की गई बैठने की व्यवस्था, आरओ एवं कूलर युक्त पेयजल सुविधा तथा क्रू सदस्यों के लिए शतरंज एवं कैरम जैसी मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुंबई सेंट्रल मंडल में उपनगरीय खंड में 12 वातानुकूलित रनिंग रूम भी उपलब्ध हैं, जहां मोटरमैन

एवं ट्रेन मैनेजर दो ड्यूटी सेटों के बीच रात्रिकालीन ठहराव के दौरान विश्राम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, चर्चगेट, बोरीवली एवं विरार लॉबी में योग कक्ष-सह-शांति कक्ष भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कर्मचारियों को विश्राम, ध्यान एवं तनाव प्रबंधन में सहायता मिल सके। इन सुविधाओं का उद्देश्य ड्यूटी चक्र के दौरान क्रू सदस्यों को शांत एवं सहयोगात्मक वातावरण प्रदान करना है।

श्री विनीत अभिषेक ने आगे बताया कि उपनगरीय क्रू के लिए विश्राम व्यवस्था निर्धारित मानकों से अधिक है। एचओईआर (HOER) प्रावधानों के अनुसार, क्रू सदस्यों को प्रतिमाह कम से कम 30 घंटे के चार विश्राम अथवा 22 घंटे के पांच विश्राम दिए जाने आवश्यक हैं। जबकि पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल में मोटरमैन एवं ट्रेन मैनेजरों की कार्य अनुसूची में प्रतिमाह 22 घंटे के 8 से 9 विश्राम दिए जाते हैं, जो निर्धारित मानक से अधिक है।

मोटरमैनों को सुरक्षित कार्यप्रणाली, ध्यान एवं तनाव प्रबंधन के संबंध में काउंसलिंग प्रदान करने हेतु चर्चगेट एवं बोरीवली लॉबी में प्रत्येक माह नियमित संरक्षा सेमिनार का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा, जगजीवन राम अस्पताल के मनोचिकित्सकों को उपनगरीय लॉबी में तनाव प्रबंधन एवं राहत सत्र आयोजित करने हेतु नामित किया गया है।

समग्र कल्याणकारी दृष्टिकोण के अंतर्गत मोटरमैनों के परिवारजनों के लिए पारिवारिक सेमिनार का भी आयोजन किया जाता है। इन सत्रों के माध्यम से स्वस्थ संवाद को बढ़ावा देने तथा चौबीसों घंटे उपनगरीय संचालन में कार्यरत क्रू सदस्यों के लिए पारिवारिक सहयोग को प्रोत्साहित करने का अवसर मिलता है। ऐसे कार्यक्रमों के दौरान चिकित्सा विशेषज्ञ परिवारजनों को सीपीआर, प्राथमिक उपचार, चिकित्सीय आपात स्थितियों में प्रतिक्रिया तथा सामान्य शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता की जानकारी भी देते हैं।

श्चिम रेलवे द्वारा निरंतर काउंसलिंग, सुरक्षित कार्य संबंधी मार्गदर्शन, चिकित्सा जागरूकता तथा क्रू सदस्यों के साथ नियमित संवाद पर भी विशेष बल दिया जाता है। इन पहलों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि मोटरमैन एवं ट्रेन मैनेजरों को केवल आधारभूत सुविधाएं एवं विश्राम ही नहीं, बल्कि प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं स्वास्थ्य संबंधी सहयोग भी प्राप्त हो। सुरक्षित ट्रेन संचालन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मोटरमैनों को उपयुक्त स्तर पर पुरस्कृत भी किया जाता है।

निर्धारित मानकों के अनुसार मोटरमैन एवं ट्रेन मैनेजरों की समय-समय पर चिकित्सीय जांच भी की जाती है। 45 वर्ष की आयु तक प्रत्येक चार वर्ष में एक बार, 55 वर्ष की आयु तक प्रत्येक दो वर्ष में एक बार तथा 55 वर्ष की आयु के बाद प्रतिवर्ष चिकित्सा परीक्षण किया जाता है। प्रशासन ने पुनः दोहराया है कि कर्मचारियों का कल्याण, पर्याप्त विश्राम, काउंसलिंग सहायता, चिकित्सा सुविधा एवं सुरक्षित कार्य वातावरण पश्चिम रेलवे की प्राथमिकताएं हैं।

पश्चिम रेलवे, लाखों यात्रियों के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय एवं कुशल उपनगरीय ट्रेन परिचालन सुनिश्चित करते हुए, भविष्य में भी क्रू सदस्यों एवं उनके परिवारों के साथ नियमित संवाद बनाए रखेगी।

सोमनाथ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना में होटल एवं आतिथ्य व्यवसाय हेतु वाणिज्यिक अवसरों पर विचार-विमर्श

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के अंतर्गत पुनर्विकासाधीन सोमनाथ रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध कराए जा रहे वाणिज्यिक क्षेत्र के उपयोग एवं राजस्व सृजन की संभावनाओं पर विचार-विमर्श हेतु अपर मंडल रेल प्रबंधक (एडीआरएम) श्री ऋत्विक शर्मा, भावनगर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का समन्वय वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, भावनगर श्री अतुल कुमार त्रिपाठी द्वारा किया गया, जिसमें होटल एवं रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठित व्यवसायियों एवं प्रबंधकों ने भाग लिया।

बैठक में सोमनाथ रेलवे स्टेशन के स्टेशन भवन की तृतीय एवं चतुर्थ मंजिल पर उपलब्ध लगभग 6000 वर्गमीटर क्षेत्र को दीर्घकालिक लीज के आधार पर होटल एवं आतिथ्य व्यवसाय के विकास हेतु उपयोग में लाने के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई।

सोमनाथ रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य लगभग 157 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता के वाणिज्यिक अवसंरचना का भी विकास किया जा रहा है, जिससे यात्रियों एवं पर्यटकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

बैठक के दौरान उपस्थित हितधारकों को प्रस्तावित अवसंरचना, सोमनाथ क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं तथा उपलब्ध वाणिज्यिक अवसरों पर आधारित एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिखाया गया।

हितधारकों ने परियोजना की व्यावसायिक व्यवहार्यता के संबंध में यात्री प्रोफाइल विश्लेषण, पर्यटकों के ठहराव की संभावनाओं, होटल नियोजन तथा संचालन संबंधी विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए। साथ ही सोमनाथ, द्वारका एवं गिर को जोड़ने वाले एकीकृत पर्यटन परिपथ (टूरिस्ट सर्किट) विकसित करने के सुझावों पर भी चर्चा की गई।

रेलवे अधिकारियों ने जानकारी दी कि स्टेशन परिसर में आवश्यक मूलभूत संरचनात्मक सुविधाएं एवं उपयोगिता सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जबकि होटल एवं आतिथ्य क्षेत्र के लिए आंतरिक विकास कार्य इच्छुक निवेशकों द्वारा अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा।

वर्मा ने बताया कि यह पहल न केवल सोमनाथ क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि रेलवे के लिए गैर-किराया राजस्व (नॉन-फेयर रेवेन्यू) में भी महत्वपूर्ण वृद्धि सुनिश्चित करेगी।

यात्रियों की सुविधा हेतु भावनगर मंडल की कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के समय में संशोधन

यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा रेल संचालन को अधिक सुगम, व्यवस्थित एवं समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे ने भावनगर मंडल से संचालित होने वाली कई महत्वपूर्ण यात्री ट्रेनों के समय में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों की संशोधित समय सारिणी क्रमशः 23 एवं 24 मई, 2026 से प्रभावी होगी। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार निम्नलिखित ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है—

1. ट्रेन संख्या 22990 महुवा–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस के समय में संशोधन 23 मई, 2026 से प्रभावी होगा। यह ट्रेन महुवा से वर्तमान निर्धारित समय 17:55 बजे के स्थान पर 17:30 बजे प्रस्थान करेगी। अर्थात यह ट्रेन महुवा से 25 मिनट पूर्व रवाना होगी। इसके अतिरिक्त राजुला जंक्शन, सावरकुंडला तथा लीलीया मोटा स्टेशनों के समय में भी परिवर्तन किया गया है। इसके आगे के स्टेशनों के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

2. ट्रेन संख्या 19256 महुवा–सूरत एक्सप्रेस के समय में संशोधन 24 मई, 2026 से प्रभावी होगा। यह ट्रेन महुवा से वर्तमान निर्धारित समय 17:55 बजे के स्थान पर 17:30 बजे प्रस्थान करेगी। इस प्रकार यह ट्रेन भी महुवा से 25 मिनट पूर्व चलेगी। राजुला जंक्शन, सावरकुंडला, लीलीया मोटा तथा दामनगर स्टेशनों के समय में भी परिवर्तन किया गया है। इसके आगे के

स्टेशनों के समय यथावत रहेंगे।

3. ट्रेन संख्या 20966 भावनगर टर्मिनस–साबरमती इंटरसिटी एक्सप्रेस के समय में संशोधन 23 मई, 2026 से प्रभावी होगा। इस ट्रेन के भावनगर टर्मिनस से धोला स्टेशन तक के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बोटाद स्टेशन से यह ट्रेन वर्तमान निर्धारित समय 07:25 बजे के स्थान पर 07:39 बजे प्रस्थान करेगी। इसके फलस्वरूप आगे के स्टेशनों के समय में भी परिवर्तन किया गया है।

4. ट्रेन संख्या 09215/09216 भावनगर–गांधीग्राम–भावनगर TOD स्पेशल के समय में संशोधन 23 मई, 2026 से प्रभावी होगा।

ट्रेन संख्या 09215 गांधीग्राम–भावनगर TOD स्पेशल के धंधुका, बोटाद एवं धोला स्टेशनों के समय में मामूली परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन गांधीग्राम से अपने निर्धारित समय पर प्रस्थान करेगी तथा भावनगर टर्मिनस पर वर्तमान निर्धारित समयानुसार ही पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 09216 भावनगर–गांधीग्राम TOD स्पेशल के प्रारंभिक प्रस्थान समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सिहोर स्टेशन से प्रस्थान समय में मामूली परिवर्तन के कारण आगे के स्टेशनों के समय में भी संशोधन किया गया है।

5. ट्रेन संख्या 09211 गांधीग्राम–बोटाद TOD स्पेशल के समय में संशोधन 23 मई, 2026 से प्रभावी होगा। गांधीग्राम से प्रस्थान समय यथावत रहेगा। सरखेज से आगे के स्टेशनों के प्रस्थान समय में मामूली परिवर्तन किया गया है।

6. ट्रेन संख्या 09529/09530 भावनगर–धोला–भावनगर TOD स्पेशल के समय में संशोधन 24 मई, 2026 से प्रभावी होगा।

ट्रेन संख्या 09529 धोला–भावनगर TOD स्पेशल धोला से वर्तमान निर्धारित समय 11:50 बजे के स्थान पर 11:30 बजे प्रस्थान करेगी।

ट्रेन संख्या 09530 भावनगर–धोला TOD स्पेशल भावनगर टर्मिनस से वर्तमान निर्धारित समय 13:25 बजे के स्थान पर 13:15 बजे प्रस्थान करेगी।

दोनों दिशाओं में आगे के स्टेशनों के आगमन एवं प्रस्थान समय में भी आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया गया है। संशोधित समय सारिणी के अनुसार उपरोक्त ट्रेनों के आगमन एवं प्रस्थान समय में किए गए परिवर्तन से यात्रियों को अधिक सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्राप्त होगा तथा रेल परिचालन की दक्षता में भी सुधार होगा। विशेष रूप से महुवा, भावनगर, बोटाद, गांधीग्राम, साबरमती, सूरत तथा बांद्रा टर्मिनस के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व संबंधित ट्रेनों के संशोधित समय की जानकारी रेलवे पूछताछ सेवा, NTES (National Train Enquiry System), IRCTC Rail Connect ऐप अथवा निकटतम रेलवे स्टेशन से अवश्य प्राप्त कर लें। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने कहा कि पश्चिम रेलवे यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं समयनिष्ठ रेल सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से 'कल्पसर परियोजना' को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट 'कल्पसर प्रोजेक्ट' को मिले नीदरलैंड की तकनीक के नए पंख

गुजरात की पानी की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी कल्पसर परियोजना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नीदरलैंड दौरे के दौरान कल्पसर परियोजना के लिए तकनीकी सहयोग को लेकर आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए

गुजरात को जल संसाधन के क्षेत्र में नीदरलैंड के तकनीकी सहयोग और विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा

सरदार सरोवर बांध पर निर्भरता होगी कम, पेयजल और सिंचाई के लिए सुनिश्चित होगी जल की व्यापक उपलब्धता

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। नीदरलैंड के अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री श्री रॉब जेटेन के साथ नीदरलैंड की प्रसिद्ध जल प्रबंधन संरचना, 'अफस्लुइटडिज्क' (Afsluitdijk) का दौरा किया। उन्होंने इस बांध में इस्तेमाल की गई तकनीक को सीखने योग्य बताया।

उल्लेखनीय बात यह है कि 'अफस्लुइटडिज्क' और गुजरात की कल्पसर परियोजना के बीच बहुत-सी समानताएं हैं। कल्पसर परियोजना पर तकनीकी सहयोग के लिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भारत के जल शक्ति मंत्रालय और नीदरलैंड के बुनियादी ढांचा और जल प्रबंधन मंत्रालय के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इससे परियोजना का कार्य तेज रफ्तार से आगे बढ़ने के नए द्वार खुल गए हैं।

अनियमित वर्षा और सूखे की समस्या से वर्षों से जूझ रहे गुजरात को सरदार सरोवर बांध के निर्माण से राहत तो मिली है, लेकिन दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी एक परियोजना पर ही निर्भर रहना जोखिम ही कहा जा सकता है। इसीलिए, तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने खंभात की खाड़ी में महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना की संकल्पना की थी। हालांकि, यह परियोजना तकनीकी रूप से अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण है।

क्या है कल्पसर परियोजना

कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी में एक विशाल बांध का निर्माण कर समुद्र में गिर रहीं सात नदियों के पानी का उपयोग करने की योजना है। इस योजना का उद्देश्य खंभात की खाड़ी पर मीठे पानी का एक विशाल जलाशय बनाना है, जिसमें ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन, सिंचाई और परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर का एकीकृत विकास शामिल है।

वर्ष 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से कल्पसर बांध की पथरेखा सुनिश्चित करने के लिए भावनगर में समुद्री सर्वेक्षण का ऐतिहासिक शुभारंभ किया गया। लेकिन, योजना के बेहद जटिल होने के कारण इसे साकार करने में कई प्रकार की

मुश्किलें सामने आ रही हैं। इन मुश्किलों से निपटने के लिए सरकार की ओर से लगातार ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में, 30 मार्च, 2026 को गांधीनगर में नीदरलैंड की राजदूत सुश्री मारिसा गेराड्स से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कल्पसर योजना को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की और 'इंडो-डच' विशेषज्ञ समूह के गठन और जी2जी भागीदारी के बारे में चर्चा की।

कल्पसर परियोजना से मिलेंगे ये लाभ

कल्पसर परियोजना के साकार होने पर सौराष्ट्र के 9 जिलों की 42 तहसीलों को लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलेगा। इस योजना से दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के बीच की दूरी 240 किलोमीटर से कम होकर 60 किलोमीटर रह जाएगी। इतना ही नहीं, योजना से लगभग 1500 मेगावाट पवन ऊर्जा और 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। योजना से पर्यटन और मत्स्य पालन का विकास भी सुनिश्चित होगा।

कल्पसर परियोजना को साकार करने के लिए समय-समय पर विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट भी तैयार की गई हैं। कल्पसर परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 'क्लोजर मेथडोलॉजी' में नीदरलैंड के समुद्री क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाले विश्व प्रसिद्ध संस्थान 'रॉयल हास्कोनिंग' ने काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है।

क्या है 'अफस्लुइटडिज्क'

'अफस्लुइटडिज्क' नीदरलैंड ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे मशहूर इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक है। यह दुनिया के लिए जल प्रबंधन का एक शानदार उदाहरण है। इसका निर्माण लगभग 80 साल पहले किया गया था। ये 32 किलोमीटर लंबा बैरियर डैम उत्तरी सागर को मीठे पानी की झील से अलग करता है। साथ ही, यह बांध नीदरलैंड के निचले इलाकों के बड़े हिस्से को भारी बाढ़ से बचाता है, यही वजह है कि इसे बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक मानक माना जाता है।

इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह समुद्र के खारे पानी को रोककर अंदर मीठे पानी का एक बहुत बड़ा जलाशय बनाता है। 'अफस्लुइटडिज्क' परियोजना में मीठे पानी के भंडारण के अलावा जहाजरानी, परिवहन संपर्क और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन भी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री का दृढ़ संकल्प और नीदरलैंड की भागीदारी करेगी कल्पसर परियोजना को साकार

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सदैव दीर्घकालीन और बड़े लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते हैं। गुजरात में अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान उन्होंने कल्पसर परियोजना का स्वप्न देखा था। राज्य को जल संकट की स्थिति से बाहर निकालकर जल समृद्ध बनाने के संकल्प के साथ उन्होंने सरदार सरोवर बांध जैसी विराट परियोजना को धरातल पर उतारा। दशकों तक राजनीतिक और पर्यावरणीय अवरोधों का सामना कर रही सरदार सरोवर योजना को साकार करने के लिए उन्होंने अदम्य इच्छा शक्ति और फौलादी संकल्प का परिचय दिया।